do not think there is any confusion, any sentiment or anything of that kind in that. It is only to commemorate the victory of the Azad Hind Fauj by whom these islands were conquered. If there is any confusion or any wounding of the feelings, it is of the hon. Minister's and nobody else's.

**Mr. Deputy-Speaker:** Let us remove that confusion now.

**The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha):** Time is up.

**Mr. Deputy-Speaker:** Has he concluded?

**Shri Subiman Ghose:** What I had originally thought was that I shall not withdraw the Resolution. But I think that the Government is not adamant in not accepting it and keeps an open mind. I thought that the Tripuri episode had been forgotten but I think up till now that has not been forgotten. In view of that I withdraw the Resolution.

**Mr. Deputy-Speaker:** Is Shri Chaudhuri willing to withdraw his amendment?

**Shri Tridib Kumar Chaudhuri:** Yes, Sir.

**Mr. Deputy-Speaker:** Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment?

*The amendment was, by leave, withdrawn.*

**Mr. Deputy-Speaker:** Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his Resolution?

*The Resolution was, by leave withdrawn.*

---

**16.46 hrs.**

## RESOLUTION RE. DEVELOPMENT OF BACKWARD AREAS IN THE THIRD FIVE YEAR PLAN

standard."

**Shri M. L. Dwivedi** (Hamirpur): Sir, I beg to move:

"This House is of opinion that while preparing the Draft of the Third Five Year Plan special attention be paid to ensure that the pace of development is greater in backward areas than in other areas and that this arrangement should continue till all the backward areas are uniformly developed upto a certain basic standard."

जो यह संकल्प मैं सदन के सामने रख रहा हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सम्बन्ध देश की आधे से अधिक आबादी और क्षेत्र से है। हमारा योजना आयोग और हमारी केन्द्रीय सरकार बारम्बार यह आश्वासन दे चुके हैं कि हम पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। मैं यहां पर दूसरी योजना में से एक पैरा पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं जिससे आपको विदित होगा कि इस बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या मत था। इस में कहा गया है :—

"It is axiomatic that the special needs of the less developed areas should receive due attention."

लेकिन हुआ यह कि इस ओर सरकार ने कोई तवज्जह नहीं दी और हम देखते रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े काम योजना आयोग के द्वारा हो रहे हैं, जिन पर लाखों, करोड़ों और अरबों रुपया खर्च हो रहा है, वे सब के सब विकास के काम ऐसे क्षेत्रों में हो रहे हैं जो पहले से ही विकसित हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन क्षेत्रों का विकास न किया जाए लेकिन जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनको जब तक आप दूसरे विकसित क्षेत्रों की बराबरी पर नहीं लायेंगे, समानता पर नहीं लायेंगे, वे पिछड़े हुए अंग बने रहेंगे और इस बात को कहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी प्लानिंग की मिनिस्ट्री या योजना आयोग कूबड़ सुन्दरी के समान है कि जो अपने कूबड़ को तो छिपाती है लेकिन आंखों में काजल डालती है, होंठों पर लिपस्टिक और बालों में खुशबूदार तेल लगा कर चलना चाहती है . . .

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपको यह भी अपील नहीं करती हैं।

**श्री म० ला० द्विवेदी :** मगर मैं चाहता हूं कि उसे अपने कूबड़ की तरफ भी ध्यान

देना चाहिये । अगर आपके एक अंग में फोड़ा हो लेकिन शरीर आपका बिल्कुल तन्दरुस्त हो तो आप निश्चय मानिये कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं और वह फोड़ा आपको मजबूर कर देगा कि आप आगे नहीं जा सकते हैं । आज जब कि सारा देश विलग रहा है, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बेर की गुठली खाते हैं, मौहा खाते हैं चूंकि अन्न दुर्लभ है, घास का फल जिसको राही कहते हैं, समावर कहते हैं, कोदो कहते हैं, खाते हैं और उनको खा कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन जो बड़े बड़े नगरों से, बम्बई से या दूसरे स्थानों से लोग आते हैं, जहां पर बहुत तरक्की हो चुकी है, बहुत सा विकास का काम हो चुका है, उनका ध्यान इन सब बातों की तरफ नहीं जाता है ।

आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जितना कर भार है, वह सारे का सारा ग्रामीण जनता पर है, सारा कर-भार कृषि समाज पर है, उनकी रीढ़ की हड्डी को हम तोड़ते जा रहे हैं, उन लोगों को ऊपर उठाने की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और यह बहुत ही खतरनाक चीज है । इस बजट में और पिछले बजटों में जितने भी कर लगाये गये हैं, वे सब के सब ग्रामीण जनता पर लगाये गये हैं । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कृषिकारों की आमदनी इस समय तक दुगनी से अधिक नहीं बढ़ी है । पहले गल्ला छः रुपये मन बिकता था तो आज उसका भाव १० रुपये मन है या १२-१३ रुपये मन है, दिल्ली में उसका भाव जरूर २० रुपये मन है । इसका मतलब यह हुआ कि किसान की आमदनी दुगनी से अधिक नहीं हुई है जब कि बाकी सारी की सारी वस्तुयें पांच, छः और आठ गुना महंगी हो गई हैं । सोना जो पहले बीस रुपये तोला हुआ करता था आज १३२ और १३५ रुपये तोला है । इन सब बातों से यह जाहिर होता है कि देहात की जनता का स्तर ऊंचा नहीं उठा है और दिन-प्रति-दिन गिरता चला जा रहा है ।

विकास खंड जो खोले गए हैं उनमें ब्लाक अधिकारियों के बंगले बन कर तैयार हो जाते हैं, बगीचे लग जाते हैं लेकिन दूसरे कोई काम नहीं होते हैं और माननीय मंत्री महोदय या कर्मचारी जब जाते हैं तो उनको अच्छी चाय पीने को मिल जाती है और अच्छे बिस्कुट खाने को मिल जाते हैं, लेकिन उससे उनको यह पता नहीं चल सकता है कि उस गांव में क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है ।

एक डिवेलेपमेंट ब्लाक के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है जब उस ब्लाक में मैं गया और वहां जा कर देखा—और भी उदाहरण मैं दे सकता हूं—गौहांड में, कि डिवेलेपमेंट अधिकारियों के लिए मकान बन गए हैं, इमारतें बन गई हैं, बागीचे लग गए हैं लेकिन ग्रामीण जनता ने परिश्रम करके, श्रमदान के द्वारा वहां पर जो चार फरलांग की कच्ची सड़क बनाई थी आज तक उसको पक्का नहीं किया गया है । वहां पर आपको रंग बिरंगे काम हुए दिखा दिये जाते हैं और आप समझते हैं कि काम अच्छा हो रहा है । लेकिन वहां के जो निवासी हैं वे जानते हैं कि वहा क्या काम हो रहा है । अधिकारी लोग व्यर्थ में पैसा बरबाद कर रहे हैं । आपकी नजर में वह चीज़ नहीं आ रही है । मुलम्मा-साजी का काम कब तक आपको चकाचौंध करता रहेगा ? जो दूसरा मंत्रालय है, जिसको कम्युनिटी डिवेलेपमेंट मंत्रालय कहा जाता है, विकास खंड का मंत्रालय है उसके पास इसके बारे में कोई दलील नहीं है । आप तो केवल इतना ही कहते हैं कि वहां की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार या बम्बई की सरकार की यह जिम्मेदारी है कि देखे कि विकास खंडों का काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है । विकास खंडों के वास्ते, रुपया तो आप देते हैं, पैसा तो आप देते हैं । और यदि उस रुपये पर आप नियंत्रण नहीं रख सकते हैं तो क्यों आप रुपया देते हैं । क्यों आप काम को नहीं देखते हैं । मैंने देखा है

कि इतना अधिक रुपया बरबाद हो रहा है कि कोई अंदाजा ही नहीं। यदि योजना आयोग ने अब भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसकी चिन्ता नहीं की तो आप याद रखिये कि देश की आधी से अधिक जनता इन कामों से रुष्ट हो जाएगी और इसका पहला प्रभाव परिस्थितियों पर पड़ेगा, इसके बाद प्रभाव वोटों पर पड़ेगा। यह बात मैं चेतावनी स्वरूप सदन में ला रहा हूं और आज सदन इस बात को जज करेगा निर्णय लेगा कि सरकार जो समय समय पर आश्वासन देती है, उन को पूरी भी करती है या नहीं करती है। वह या तो उन आश्वासनों को पूरा करे और यदि पूरा नहीं करती है तो उनको वापिस ले ले।

मैं बताना चाहता हूं कि पिछड़े हुए क्षेत्र कौन से हैं। पहले तो वे क्षेत्र हैं जहां पर भूतपूर्व राजा राज करते थे, रजवाड़े थे, रियासतें थीं, जिनको देशी रियासतें कहा जाता था और उन इलाकों का क्षेत्रफल ४५ प्वांइट कुछ प्रतिशत है। वे सब के सब क्षेत्र आज भी पिछड़े हुए हैं। सरदार पटेल ने अपने एक वक्तव्य में रियासतों के बारे में जो कुछ कहा था उसको मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :—

"Where on account of smallness of its size, isolation of its situation, the inseparable link with a neighbouring autonomous territory, be it a Province or a bigger State, in practically all economic matters of every day life, the inadequacy of resources to open up its economic potentialities, the backwardness of its people and the sheer incapacity to shoulder a self-contained administration, a State is unable to afford a modern system of government both democratisation and integration are clearly and unmistakably indicated.

In the world of today where distances are fast shrinking and masses are being gradually brought into touch with latest administrative amenities, it is impossible to postpone for a day longer than necessary the introduction of measures, etc....."

यह आपके व्हाइट पेपर में है जो कि सन् १९४८ में प्रकाशित किया गया था। उसमें सरदार पटेल ने कहा था कि हम इसलिए रियासतों का विलीनीकरण कर रहे हैं कि वे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वहां की आमदनी काफी नहीं होती है। हम विकास कार्य वहां करेंगे, उनको अच्छा शासन देंगे। आज उन सारी रियासतों में आपने क्या क्या किया है, आपने उनके लिए कोई विशेष प्रोग्राम नहीं बनाया है। आप ने विकास खंड और दूसरी सभी चीजें उन इलाकों को दी हैं, जो पहले से विकसित हैं। वहां पर इतनी दिक्कतें हैं कि आपको अन्दाजा नहीं हो सकता है। एक किसान को गल्ला ले जाने के लिए १५–२० मील एक गाड़ी, दो बैल और दो आदमी साथ ले जाने पड़ते हैं, पांच पांच दिन उसको लग जाते हैं आने जाने में और अगर तीन रुपये रोज का उसका खर्चा भी लगाया जाये तो २०–२५ रुपये उसके आने जाने में खर्च हो जाते हैं। इसका आपको अन्दाजा भी नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दें। वहां पर वे काम हाथ में लें जिन से उनको लाभ पहुंच सकता है।

आप सड़कें बना रहे हैं लेकिन हालत क्या है? दो हजार मील से ऊपर दूसरी स्टेट्स में संख्या बढ़ गई है। लेकिन जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां सड़कों का निर्माण नागपुर में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, उसके मुताबिक नहीं हुआ है, उस प्रस्ताव को आप अमली रूप नहीं दे सके हैं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर चारों तरफ नदियां हैं जिन पर कोई पुल नहीं हैं। वहां पर मेरे क्षेत्र में एक भी सड़क ऐसी नहीं है कि हम ग्रामीण जनता तक पहुंच सकें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो कहीं कहीं छः छः मील तक मुझे पानी में घुस कर जाना पड़ता है, तैर कर जाना पड़ता है और इस

[श्री म० ला० द्विवेदी]

कारण यह है कि वहां पर सड़कें नहीं है। आप दिल्ली की चकाचौंध करने वाली सड़कों की तरफ न जायें, और जो ऊंची ऊंची आठ दस बारह मंजिला इमारतें बना र हैं उनकी तरफ न जायें। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रामीण जनता सुधारों के लिए तरस रही है? अगली योजना आप दस अरब रुपये की बनाने की सोच रहे हैं। उसमें निर्धारित रकम आप कहां खर्च करेंगे? क्या वह भी सब का सब रुपया शहरों पर खर्च करेंगे जहां की आबादी कुल आबादी का १७ प्रतिशत है और क्या ग्रामीण जनता पर जिसकी आबादी ८२ प्रतिशत से ऊपर है, खर्च करने का विचार नहीं कर रहे हैं? ग्रामीण जनता की ओर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। ग्रामीण जनता के आधार पर ही आपने सरकार बनाई है, ग्रामीण जनता के बल पर ही शासन चला रहे हैं और ग्रामीण जनता की ही उपेक्षा कर रहे हैं। क्या योजना आयोग या भारत सरकार को यह उचित दिखाई देता है? नन्दा जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि बजाय शहरों का दौरा करने के वह हमारे ग्रामों में आयें और वहां आ कर मुझे बतलायें कि कौन से सुधार के काम हुए हैं और अगर उन्होंने मुझे सुधार के काम बता दिये तो मैं पचास बार अपने कान पकड़ कर उठूंगा और बैठूंगा अगर मैं गलत कह रहा हूं कि वहां कोई सुधार के काम नहीं हुए हैं।

**श्री नन्दा (श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री)**: आपने कभी बुलाया ही नहीं।

**श्री म० ला० द्विवेदी**: नन्दा जी नहीं जानते हैं। मिश्र जी एक बार मठ में गए थे और वह जानते हैं कि वहां कोई स्कूल नहीं, विद्यालय नहीं

**उपाध्यक्ष महोदय**: वह कहते हैं कि आपने कभी बुलाया है?

**श्री म० ला० द्विवेदी**: हां बुलाया है। स्वामी ब्रह्मानन्द जी ने आपको पत्र भेजा था, आपके पास समय नहीं था, आप नहीं आ सके, मिश्र जी आये थे। मैं आज भी आपको निमंत्रण देता हूं कि आप आयें और देखें।

शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि आप शिक्षा की गति को कहां ले जा रहे हैं? पांच लाख विद्यार्थी आज हमारे ग्रेजुएट्स हैं। आपको मालूम नहीं कि तीन करोड़ विद्यार्थी प्राइमरी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पा रहे हैं। यदि हम सोच लें कि केवल दस प्रतिशत ही सेकेंड्री स्कूल्स में जाते हैं तो उन विद्यार्थियों की संख्या साठ लाख से ऊपर हो जाती है जो सेकेंड्री स्कूलों में पढ़ते हैं। आप बाबू बनाना चाहते हैं और बाबूगिरी के लिए आप के पास जगहें नहीं हैं, उन के लिए कोई रोजगार नहीं है। हर देश के अन्दर प्रथा है कि वहां प्राविधिक शिक्षा दी जाती है, टेकनिकल एजुकेशन दी जाती है, आप के भी जितने स्कूल हैं उन को रहने दीजिये, मैं उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन आगे आप जितने सेकेन्डरी स्कूल खोलें, जितने कालेज खोलें उन के लिए कह दीजिये कि वे प्राविधिक शिक्षा, टेकनिकल एजुकेशन के लिए खुलेंगे। अगर आप इस तरह से करेंगे तभी आप कहीं जा सकेंगे, वरना कहीं नहीं जा सकेंगे।

मैं ने बतलाया कि रियासती क्षेत्रों की हालत बहुत खराब है, और भी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक विकास नहीं किया गया। उदाहरण के लिए आसाम का पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तर बिहार का इलाका, जहां पर आज भी ऐसी बुरी हालत है कि लोग नंगे रहते हैं, उन के रहने के लिए मकान नहीं बन सके हैं। वे पहाड़ों में रहते हैं, जंगल के फल फूल खा कर रहते हैं या कच्चा मांस खाते हैं। आज यह स्थिति उत्तर बिहार में मौजूद है, आप वहां कभी देखने नहीं गये। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में जिसे बुंदेलखंड कहते हैं, मैं गया था और आप के ब्लाक इंडस्ट्रीज के हिस्सों को देख कर आया हूं और उन आदमियों से बता

कर के आया हूं जिन की स्थिति यह है। शायद श्री श्याम नन्दन मिश्र को इस का पता न हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एस्टिमेट्स कमेटी के सारे सदस्य गये थे। राजस्थान का सारा इलाका पड़ा हुआ है, उस के विकास की ओर कभी आप का ध्यान गया? लाल बहादुर जी शास्त्री ने राज्य सभा में बहस का जवाब देते हुए कहा कि हम एक्सपर्ट्स से सलाह लेते हैं। फिर वह कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं हैं तो हम कारखाने कैसे चला दें? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर जापान कैसे करता है? जापान यहां से कई हजार मील दूर लोहा ले जाता है और वहां पर लोहे का सामान बना बना कर हम को बेचता है और आप कहते हैं कि चूंकि फलां जगह लोहा नहीं है, या दूसरी चीज नहीं मिलती इसलिए हम कारखाने वहां नहीं बना सकते। आप के पास रेलें हैं, दूसरे साधन हैं। आप सड़कें बनायें, रेलें बिछायें। लेकिन रेल मंत्री डबल लाइन करेंगे दिल्ली से बम्बई तक दिल्ली से कलकत्ते तक। इलाहाबाद स्टेशन को छेनी से तोड़ तोड़ कर बिगाड़ा गया, जो कि इतनी मजबूत इमारत थी, जो सैकड़ों वर्षों तक भी बरबाद नहीं हो सकती थी, वहां इस तरह से रुपया बरबाद किया गया, आगरा स्टेशन बनाया गया, दिल्ली में भव्य भवन तैयार हो रहे हैं। क्या मतलब है इस चीज का? एक तरफ आप कहते हैं कि खाना खाया हुआ है तो क्या हुआ, लीजिये दो रसगुल्ले और खा लीजिये, मिठाई हाजिर है, भूख नहीं है तो चूरन दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सात दिन से भूखा बैठा है उस से कहते हैं कि थोड़े दिन और ठहरो, अभी खाना नहीं मिलेगा, अभी मैं एक आदमी को भोजन करा रहा हूं। यह हालत हो रही है। आप नहीं सोचते कि जहां रेलें नहीं हैं वहां रेलें क्यों नहीं जातीं, जहां सड़कें नहीं हैं वहां सड़कें क्यों नहीं जातीं, वहां रेलें क्यों नहीं ले जाई जातीं। आप नैशनल हाईवेज बना रहे हैं। वह तो पहले से ही बने हुए थे, आप ने क्या करवाया है?



लेकिन जिन क्षेत्रों में सरितायें बह रही हैं, जहां आवागमन दुर्गम है, सामान नहीं आ जा सकता, जहां बिजली नहीं है, वहां के लिए आप क्या कर रहे हैं? जहां बिजली नहीं है वहां के लिए उद्योग मंत्री कहते हैं कि चूंकि वहां बिजली नहीं है इसलिए वहां उद्योग नहीं खुल सकते। बिजली पैदा करने के लिए मेरे इलाके में एक बांध बनना था, जिस का नाम माता टीला बांध है। वह द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शामिल था। लेकिन कहा गया कि विदेशी विनिमय हमारे पास नहीं है इसलिए माता टीला बांध की बिजली योजना का काम नहीं हो सकता और वह बन्द कर दिया गया। अब कहते हैं कि चूंकि वहां बिजली नहीं है इसलिए उद्योग नहीं हो सकते। उद्योग आये कैसे जब बिजली नहीं है? बिजली के लिए हमारे पास विदेशी विनिमय नहीं है, जब कि विदेशी विनिमय में अरबों रुपया आप ने बरबाद किया है। ऐसी ऐसी चीजों में बरबाद किया है जिन्हें मैं गिनाना नहीं चाहता, न उन के सम्बन्ध में सदन का समय लेना चाहता हूं। लेकिन सब कुछ कह देना इसलिए जरूरी है कि इस समय पर देश के सामने बड़ी भारी समस्या आ गई है कि योजना आयोग तरीके से चले और योजनायें ऐसी बनाये जिन से संतुलित विकास हो। श्री लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि जांच करवाने के साधन हमारे पास नहीं हैं कि कौन से पिछड़े इलाके हैं और कौन से पिछड़े इलाके नहीं हैं। मैं ने निशान लगा रखे हैं लेकिन पढ़ने का समय नहीं है। उन्होंने २६ जनवरी को राज्य सभा में कहा था कि हमें पता नहीं कि कौन से अविकसित क्षेत्र हैं। अरे साहब अविकसित क्षेत्र का पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : २६ जनवरी को तो छुट्टी रही होगी।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : २६ फरवरी, मैं भूल गया। क्षमा करें। एक महीना हुआ। वे कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं हैं

[श्री म० ला० द्विवेदी]

जांच करवाने के। अगर साधन नहीं हैं तो हमारी सेकेन्ड फाइव इग्रर प्लैन में एक जगह लिखा है . . . .

**श्री खुशवक्त राय** (खेरी) : उसे पढ़ने का मौका है ?

**श्री म० ला० द्विवेदी** : जी हां, इस का मौका है। उस के पेज ३७ में लिखा हुआ है :

> "The National Development Council recommended that there should be continuous study of the problem of diminishing regional disparities and a suitable set of indicators of regional development evolved."

लेकिन आप ने इस बात के अध्ययन के लिए आज कदम नहीं उठाया। जब कि आप के चार चार लोहे के कारखाने बन रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, लोहा हमें चाहिए। लेकिन भाई, आप तो संतुलित विकास की बात करते हैं। आप कहते हैं कि बैलेन्स्ड डेवेलपमेंट करेंगे। क्या यही बैलेन्स्ड डेवेलपमेंट है कि पांच अरब रुपये खर्च हो जायें और पिछड़े क्षेत्रों को उस की एक बूंद भी न पहुंचे ? विकास खंडों की बात तो आप छोड़ दीजिये, विकास खंडों की बात यह है कि वह एक तमाशा है कठपुतली का, जिन में रुपया नालियों की धार के अन्दर से बह रहा है और काम नहीं हो रहा है। जिस गांव में विकास खंड खुला है, वहां के लोगों का जीवन स्तर नहीं उठा, वहां कोई उद्योग नहीं खुले। किसानों के बाकी समय के लिए, जो बचता है किसानी से, आप ने काम नहीं दिया। पढ़ने लिखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर एक विद्यार्थी आठवां दर्जा पास करने के बाद अपने घर में बैठ कर सोचता है कि वह घर का काम न करे। आप की टेकनिकल शिक्षा नदारद है। शिक्षा की सारी व्यवस्था ही गलत है। लेकिन नहीं मालूम आप के दिमाग में यह बात क्यों नहीं आती। नन्दा जी बड़े योग्य व्यक्ति हैं, श्याम नन्दन मिश्र जो बड़े योग्य व्यक्ति हैं, प्लैनिंग के जितने अधिकारी हैं, वे बड़े योग्य हैं, और यही कारण है कि कुछ अंशों में काम हुआ है, देश का कुछ विकास भी हुआ है, जिस की लोग भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। मैं भी गलत बात नहीं करूंगा। लेकिन वह विकास एकांगी होता है। एक अंग का अधिक विकास किया गया है और बाकी अंगों की चिन्ता नहीं की जा रही है। समय आ गया है कि हम इस की ओर जल्दी से विचार करें और उस का सुधार करें। ऐसी व्यवस्थायें बनायें कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में अविकसित क्षेत्रों की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय। मैं नहीं कहता कि दूसरे अंगों का विकास न किया जाय, लेकिन जब तक वह बराबर न आ जायें तब तक उन पिछड़े अंगों पर इन्टेन्सिव डेवेलपमेंट या सघन विकास किया जाय और जब वे बराबर आ जायें तो सब देश बराबर बराबर चले।

**17 hrs.**

मैं कहता हूं कि आप के पास जनशक्ति है और वह ऐसी जनशक्ति है कि उस से चाहे जो काम ले लीजिये। आज हमारे पास यह जो धन है, यह जो खजाना है उस का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उस से लाभ नहीं उठाते हैं। जिस धन का हम लाभ उठा रहे हैं वह है टैक्सों का। टैक्सों का हाल यह है कि जगह जगह पर उस की चोरी हो रही है। आप का अधिकारी वर्ग ही रुपया ले कर बड़े बड़े पूंजीपतियों की मोटरों पर घूमता है और उन से टैक्स नहीं लेता है या उन से कम टैक्स लेता है। साथ ही साथ और भी प्रकार के टैक्सेज हैं, उन को छोड़ दिया जाता है। अगर पूरी तरह से टैक्स वसूल किया जाय तो आप को टैक्स लगाने की आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन वह काम नहीं किया जा रहा है। आप योजना आयोग के हैं। आप कहेंगे कि हम से क्या मतलब, यह फाइनेन्स मिनिस्ट्री का काम है। लेकिन मैं कहता हूं कि

सब की बराबर की जिम्मेदारी है । अगर वित्त मंत्रालय ठीक से काम नहीं करता तो आप वित्त मंत्रालय को बदलिये, अगर कम्युनिटी डेवेलपमेंट की मिनिस्ट्री ठीक काम नहीं करती तो आप उसे बदलिये । जहां जरूरत हो उस का सुधार कीजिये और हर समय सरकार मिल जुल कर काम करे । एक की जिम्मेदारी दूसरे पर न डाली जाय । मैं कृषि क्षेत्र से आता हूं । आप का एक सिंचाई मंत्रालय है, दूसरे मंत्रालय हैं, विकास खंडों में वह कोशिश करते हैं कि नई किस्म की खाद का प्रयोग किया जाय, वह कोशिश करते हैं कि जापानी ढंग पर चावल पैदा किया जाय, लेकिन सिंचाई मंत्रालय कहता है कि हम पानी देंगे फलां फलां तारीख को । लेकिन दो महीने तक पानी नहीं मिलता और नर्सरी में ही चावल सूख जाता है । कपास की फसल जो पैदा की जानी है वह सूख जाती है । किसान कहता है हम से कि तुम झूठ बोलते हो, हम तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे । आप की मिनिस्ट्रीज में अगर आपसी सहयोग नहीं होगा तो हम कैसे काम चलायेंगे ? अगर इस के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार हैं तो उन्हीं राज्यों को रुपया दीजिये जो आप की इच्छा से काम करें । उन से कह दीजिये कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में किसी ऐसे राज्य को रुपया नहीं दिया जायेगा जो केन्द्रीय सरकार की सलाह से काम नहीं करता या जो तरीके से मिल जुल कर काम नहीं करेगा । अगर आप दृढ़ता पूर्वक इस चीज को करें तो कोई शक नहीं है कि काम पूरा हो सकता है । कल स्टैन्डिंग कमेटी की बैठक हुई सामुदायिक विकास मंत्रालय की, मि० डे भी वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि एक ही तरीका रह गया है समितियां स्वावलम्बी कर दी जायें ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे पास १५, १६ चिटें आई हैं और सबों में कहा गया है कि उन का इलाका बैकवर्ड है ।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : सब को मौका दिया जाय और मैं प्रार्थना करूंगा कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस पर समय बढ़ा दिया जाय । सभी सदस्यों की यह राय है कि इस पर एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जो चिटें मुझे मिल रही हैं, उस से तो सारा हिन्दुस्तान ही बैकवर्ड है ।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : सारा हिन्दुस्तान बैकवर्ड है. यह मैं मानता हूं, लेकिन आप मानेंगे कि पंजाब में भी कुछ ऐसी एरिया काफी बैकवर्ड हैं । अमृतसर है, जालंधर है, लुधियाना है, यह तो डेवेलप्ड एरिया है, लेकिन रोहतक है, हरियाना है, या जो आप का पहाड़ी इलाका है, वह अनडेवेलप्ड है । जो पंजाब की स्थिति है वही दूसरे क्षेत्रों की भी है । उपाध्यक्ष महोदय, आप तो हमारी समस्याओं को जानते हैं इसलिए मैं समझता हूं कि आप को तो इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए । मैं प्रार्थना करूंगा . . . .

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरी तो कोई आपत्ति नहीं है । मेरी आपत्ति तो यही है कि जितना वक्त है, वह सब को मिल जाय ।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं इस सम्बन्ध में प्रार्थना करता हूं कि अगर आवश्यक बातें ही मैं न कहूं तो फिर मेरा प्रस्ताव लाना ही बेकार हो जायेगा । इसलिए एक घंटा और बढ़ा दिया जाय ।

मैंने इस प्रस्ताव में यह लिखा है कि आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, तामिलनाद का कुछ एरिया है, कुछ मैसूर का एरिया है, नार्थ बिहार का कुछ एरिया है, आसाम के हिली रिजन्स हैं, मध्य प्रदेश का वह भाग जो मालवा को छोड़ कर बैकवर्ड है, इसी तरह से पूर्वी और दक्षिणी आसाम का एरिया है जो कि बैकवर्ड है, सेंट्रली ऐडमिनिस्टर्ड एरियाज में हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अन्दमान इत्यादि हैं, जो कि बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और इन की तरफ विशेष तवज्जह देने की आवश्यकता है ।

[श्री म० ला० द्विवेदी]

इस के पश्चात् भारत सरकार का इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन है, उस की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उस इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन में यह लिखा है :

"In order that industrialisation may benefit the economy of the country as a whole, it is important that disparities in levels of development between different regions should be progressively reduced. The lack of industries in different parts of the country is very often determined by factors such as the availability of the necessary raw materials or other natural resources......It is one of the aims of national planning to ensure that these facilities are steadily made available to areas which are at present lagging behind industrially or where there is greater need for providing opportunities for employment....".

यह ठीक है कि हमारी सरकारों ने इस बात पर पूरा जोर दिया है। अब कुछ काम होने वाला है लेकिन १२ साल बीत गये और काम संतोषप्रद ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और चाहता हूं कि मंत्री महोदय अब इस की अधिक उपेक्षा न कर के शीघ्र ही वह दिन लायें जिस में कि पिछड़े हुए इलाके और अविकसित इलाके भी स्वतंत्रता प्राप्ति के उस सुख का अनुभव कर सकें जिसकी कि वह इतने दिनों से आकांक्षा कर रहे थे।

अब मैं एक, दो बातें कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। एक बात तो यह कहनी है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कर रहे हैं, उद्योग बैठा रहे हैं वे सब बड़े बड़े शहरों में ही केन्द्रित करते जा रहे हैं। बंगलौर में ४, ४ बड़े कारखाने हैं, मद्रास में १० होंगे और बम्बई में ८० के लगभग कारखाने बन चुके हैं। यह जो कारखाने एक ही जगह पर बनते जा रहे हैं तो इन को डिसेंट्रलाइज करिये, अलग अलग इकाइयां बनाइये। अविकसित क्षेत्रों में कारखाने बनाइये। जब तक आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक पता चलने वाला नहीं है। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को कायम करने के स्थान तलाश करिये कि जहां पर कच्चा सामान भी हो और जहां कि यह उद्योग स्थापित करके उन क्षेत्रों को विकसित किया जा सके। अब विन्ध्य प्रदेश को ही ले लीजिये। विन्ध्य प्रदेश के लिए कहा है कि Vindhya Pradesh is the epitome of the mineral resources of India. अब वहां पर कोल है, माइका है, मैंगनीज है, आयरन है, बौक्साइट है और पचासियों खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। बिजावल के पास पहाड़ों से लुहार पत्थर लाकर मामूली भट्टी में लोहा बनाते हैं। ८० फीसदी उस में लोहा है लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उस इलाके में हालांकि इतने मिनरल्स पाये जाते हैं लेकिन आपके जुओलाजिकल सर्वे के आदमी वहां नहीं पहुंचे और न वहां और काम हो रहा है। मैं नहीं समझ पाता कि क्या कारण है। साधन भी मौजूद हैं, रिसोर्सेज भी वहां पर हैं तो भी वहां पर काम नहीं हो पा रहा है। जैसा कि प्लानिंग कमिशन ने कहा है अब समय आ गया है कि आप एक सिटिंग कौनटीनुएस बोर्ड आफ स्टडी बना दें जो कि इन सारे बैकवर्ड ऐरियाज में इन चीजों के बारे में जांच पड़ताल करता रहे और आवश्यक सूचनायें समय समय पर सरकार को भेजता रहे। मैं चाहता हूं कि यह बोर्ड स्थायी हो और यह बराबर अपना काम जारी रक्खे। सेकेंड फाइव इयर प्लान में इस के बारे में जिक्र किया गया था और यह ठीक है कि आज इस तरह के स्टडी बोर्ड की बहुत आवश्यकता है। आप ने उस को पूरा नहीं किया है और एक ऐसा बोर्ड स्थापित नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये और यदि वह ऐसा करती है तो यह संतोष की बात होगी।

इसी तरह से छोटे छोटे उद्योग जगह जगह पर ग्राप बैठा लें। ग्रब पावर के बारे में शार्टेज है तो पहाड़ों पर जहां कि पानी भरता है ग्रौर चूंकि वहां पर सिंचाई नहीं हो सकती है इसलिये वहां पर बिजली बैठा दीजिये ग्रौर बिजली पैदा कीजिये। ग्रब जहां पर यह ग्राप की हाइड्रो एलेक्ट्रिक नहीं पहुंच सकती है तो वहां पर थर्मल पावर ग्रौर एटोमिक पावर कायम कीजिये। ग्रब दिल्ली में हाइड्रो इलेक्ट्रिक लगाने की क्या ग्रावश्यकता है ? ग्रब ग्राप के पास एटैमिक एनर्जी ग्राने वाली है चूंकि शहर के लोग ज्यादा पे करते हैं। ग्रब शहरों को थर्मल पावर ग्रौर एटैमिक पावर दीजिये ग्रौर यह हाइडल पावर देहातों को दे दीजिये। ग्रब यह क्या कि नांगल से पावर भी दिल्ली में ग्रा जाय ग्रौर हाइडल पावर भी दिल्ली में ग्रा जाय ? दिल्ली के लोगों को तो ६–६ पैसे में ग्रौर साढ़े तीन ग्राने में बिजली दी जाय ग्रौर हमारे देहाती, ग्रविकसित ग्रौर पिछड़े इलाकों को ८–९ ग्राने पर यूनिट के हिसाब से बिजली सप्लाई करते हैं तो इतनी महंगी दर में जो बिजली हम को सप्लाई की जाती है उस से कोई कारखाना नहीं चल सकता है। ग्रगर ग्राप उन ग्रविकसित क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं ग्रौर उन का ग्रौद्योगीकरण करना चाहते हैं तो ग्राप को बिजली की सुविधा ग्रौर वह भी सस्ते दर पर उन को सुलभ करनी चाहिये। ग्राप उन को हाइड्रो एलेक्ट्रिक दीजिये, एटैमिक एनर्जी के स्टेशन्स बजाये बड़े बड़े शहरों जैसे बम्बई, कलकत्ता ग्रौर दिल्ली में न बना कर देहातों में बनाइये ग्रौर ऐसा करने से हम ग्रपने प्रयास में सफल हो सकेंगे। इसी तरीके से कंज्यूमर्स गुड्स के ग्रार्टिकिल्स के वास्ते देहातों में उद्योग स्थापित कीजिये ग्रौर इस के लिये ग्राप ग्रावश्यक ट्रेनिंग दीजिये ग्रौर इस बात की कोशिश की जाय कि कोई भी उद्योग बड़े शहरों में न खुल कर देहातों में खुलेगा। ग्रगर ग्राप यह तय कर लेंगे तो ग्राप का काम चल पड़ेगा। पिछड़े इलाके खुशहाल हो सकेंगे, लोगों में ग्राज जो बेरोजगारी ग्रौर बेकारी है वह दूर हो सकेगी ग्रौर लोगों को काम मिल सकेगा।

इसी तरह से रोड ट्रान्सपोर्ट की दिक्कतें हैं। यहां भी बड़े बड़े शहरों ग्रौर विकसित इलाकों में ही देखने में ग्राता है कि ट्रान्सपोर्ट की सुविधायें बढ़ती जाती हैं लेकिन जो पिछड़े इलाके हैं उन में ट्रान्सपोर्ट की सुविधायें देने की ग्रोर कम ध्यान दिया जाता है ग्रौर उन की एक तरह से उपेक्षा ही की जाती है। हालांकि इस सम्बन्ध में नागपुर का रेजोलूशन है लेकिन मैं ग्राप को बतलाऊं कि स्टेट्समैन ग्रखबार में उत्तर प्रदेश की बाबत लिखा है ग्रौर उस की कटिंग मेरे पास मौजूद है ग्रौर जिस में कि यह दिया हुग्रा है कि दो हजार मील की कमी ग्रभी भी उत्तर प्रदेश में है, यह कमी उत्तर प्रदेश के उस भाग में नहीं है जहां के कि मंत्रीगण हैं या जहां की ग्रावाज प्रबल है बल्कि यह कमी उत्तर प्रदेश के उस पिछड़े हुए इलाके में है जिस की कि ग्रोर उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान नहीं जाता है। मतों के बलाबल पर वहां काम किया जाता है। ग्रब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चूंकि चरण सिंह मंत्री हैं इसलिये जाहिर है कि सारे का सारा विकास कार्य मेरठ की तरफ चला जायगा। इसी तरह बनारस के चूंकि श्री कमलापति त्रिपाठ मंत्री हैं इसलिये बनारस की ग्रोर ही सारा विकास कार्य चला जायगा। जाहिर है कि दक्षिण की ग्रोर कोई विकास कार्य नहीं होगा। भूपाल बढ़ रहा है। हमारे विन्ध्य प्रदेश का ग्वालियर रीजन बुंदेलखंड का इलाका जिस को कि महाकौशल कहते हैं वह इलाका बिलकुल ग्रविकसित है। वहां के मंत्री लोग मूंछों पर ताव दे कर चले जाते हैं। उन को इन पिछड़े इलाकों की ग्रब ग्रौर ग्रधिक उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ग्रौर

[श्री म० ला० द्विवेदी]

वहां पर विकास कार्य अविलम्ब शुरू कर देना चाहिये।

**श्री खुशवक्त राय** : श्री मोहन लाल गौतम अलीगढ़ के हैं ....

**श्री म० ला० द्विवेदी** : अलीगढ़ का भी जिक्र करूंगा। अलीगढ़ के बारे में भी वही बात लागू होती है जोकि बनारस और मेरठ के लिये मैं ने कही। अविकसित क्षेत्रों की ओर जो अब तक सरकार की उपेक्षा रही है वह हटनी चाहिये। अब मैं यह चाहता हूं कि मेरे जो दूसरे मित्र लोग हैं वे अपनी अपनी बातें सुनायें। मुझे जो कुछ और कहना होगा वह जब मुझे आखिर में मौका बोलने का मिलेगा तब निवेदन कर दूंगा। मैं आज इस बात से खुश हूं कि हमें उपाध्यक्ष महोदय ने एक मौका दिया कि हम पिछड़े इलाकों की बात कह सकें और इस की ओर सरकार की और प्लानिंग मिनिस्टर की तवज्जह दिला सके। देश आज सरकार से इस बात की आकांक्षा करता है कि शीघ्र से शीघ्र पिछड़े हुए इलाकों को विकसित किया जाय और आप देखेंगे कि उस इलाके के लोग आप का चीन से यदि जरूरत पड़ी तो मुकाबला करने में साथ देंगे। वे हर कठिनाई में आप के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे और आप की मदद करेंगे। पिछड़े हुए इलाकों के लोग जवांमर्द हैं, उन की बाजू में ताकत है और यकीन रखिये कि वे आड़े वक्त में आप के काम आयेंगे और संकट के अवसर पर वे अपनी जान की बाजी लगा कर भी देश की रक्षा करेंगे.. .

**उपाध्यक्ष महोदय** : अकेले क्या वही लोग काम आयेंगे दूसरे क्या काम नहीं आयेंगे ?

**श्री म० ला० द्विवेदी** : जी दूसरे लोग भी काम आयेंगे लेकिन वे अधिक काम आयेंगे लेकिन इस का यह मतलब कदापि नहीं है कि मैं उन पंजाब के वीरों की किसी तरह भी निन्दा करना चाहता हूं जिन्हों ने कि हमारा डंका और झंडा सदा ऊंचे बनाये रक्खा, जिन वीरों ने कि हमारे देश का नाम उज्ज्वल किया है, जैसे झांसी का इलाका जहां कि महारानी झांसी ने झंडा ऊंचा किया, कुंवर सिंह का इलाका जहां कि उन्हों ने स्वाधीनता की ज्योति जलाई और इसी तरह दक्षिण में, उत्तर में अन्य इलाके जहां के वीरों ने भारत की स्वाधीनता के हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और जो इलाके कि अभी तक अविकसित पड़े हैं उन में विकास कार्य सरकार शीघ्र आरम्भ कराये। इन तमाम वीरों ने अंग्रजों का मुकाबला किया था। आज अंग्रज तो इस देश से चले गये हैं लेकिन यह खेद का विषय है कि हमारी अपनी सरकार अभी तक उसी अंग्रजी सरकार की पुरानी लकीर पर ही चल रही है। अंग्रजों ने कलकत्ता पोर्ट, बम्बई पोर्ट और दिल्ली इन तीन स्थानों पर तमाम विकास कार्य किये, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किये, रेलें चलाईं और अन्य विकास कार्य किये। लेकिन अब तो अंग्रेज़ चले गये हैं और अपनी आजाद सरकार कायम है तो यह जरूरी है कि अविकसित और पिछड़े इलाकों को विकसित कर के इस बात का प्रमाण दिया जाय कि कांग्रेस गवर्नमेंट जनता के लिये है और जनता के लिये काम कर रही है। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं।

**Mr. Deputy-Speaker**: Resolution moved:

"This House is of opinion that while preparing the Draft of the Third Five Year Plan special attention be paid to ensure that the pace of development is greater in backward areas than in other areas and that this arrangement should continue till all the backward areas are uniformly developed up to a certain basic standard.".

There are certain amendments which have been tabled to this resolution. The first one is in the name of Shri Bibhuti Mishra. Is the hon. Member moving it?

**Shri Bibhuti Mishra** (Bagaha): Yes. I beg to move:

"*For* the original Resolution, *substitute*:

"This House is of opinion that while preparing the Draft of the Third Five Year Plan attention be paid to ensure that the pace of development is greater in backward rural areas than in other areas and cities and that this arrangement should continue till all the backward areas are generally developed at least up to a certain basic standard.". (1)

**Shri Narayanankutty Menon:** (Mukandapuram): I beg to move:

"*For* the original Resolution, *substitute*:

"This House is of opinion that top priority should be given to backward areas, in location of heavy industries and in allocation of other developmental expenditure.". (7).

**Mr. Deputy-Speaker:** As regards amendment No. 8, Shri Daljit Singh is absent. As regards amendment No. 2 tabled by Shri M. C. Jain, it is out of order. This is a Resolution concerning backward areas, not backward classes.

**Shri M. C. Jain** (Kaithal): I may be given a chance to speak.

**Mr. Deputy-Speaker:** That is a different thing altogether. Amendments Nos. 3 and 5 tabled by Shri M. C. Jain are also out of order for the same reasons applying to amendment No. 2.

**Shri Ram Krishan Gupta** (Mahendragarh): I beg to move:

In the Resolution, *after* the words "than in other areas" *insert*—

"and a Commission be appinted for the demarcation of backward areas in the country and suggest ways and means for improving condition." (4)

**Shri S. M. Banerjee** (Kanpur): I beg to move:

In the Resolution, *add* at the end—

"and to achieve this end a Committee be formed comprising of representatives of Lok Sabha and State Legislatures, economists and agriculturists which may advise the Planning Commission in this regard". (6)

**Mr. Deputy-Speaker:** As regards amendment No. 9, Shri Mahanty is absent.

All these amendments which have been moved together with the original Resolution are before the House. I have received chits from hon. Members and I also find hon. Members rising in their seats. There is a very large number of hon. Members who want to participate. I think a limit of 10 minutes to speeches should be observed.

**Shri Rane** (Buldana): Yes, 10 minutes.

**Some Hon. Members:** 15 minutes.

**Pandit Thakur Das Bhargava:** (Hissar): Those who have not sent chits may also be given an opportunity to speak.

**Mr. Deputy-Speaker:** Yes. I said I have received chits and also I find hon. Members rising in their seats. There would be a time-limit of 15 minutes to each Member.

**An Hon. Member:** It is a very important Resolution.

**Shri Narayanankutty Menon:** It is a tragedy for this House that a Resolution of such a character has to be discussed because it presupposes that when the formulation of the Third Five Year Plan takes place, special importance and consideration should be given to backward areas. 'Backward areas' obviously mean areas which have become backward because of the implementation of the First and Second Five Year Plans. That is inherent in the Resolution.

Planning presupposes not only planned development of industries, not only planned development of agriculture but planned development of all the nation-building activities by leaving an equitable distribution of these activities in various parts of the country. That is not only essential for the successful outcome of a planned economy, but for the successful outcome of both the emotional and the other integration of India as a nation.

When a similar Resolution was moved in the other House in the last session, the hon. Minister of Commerce and Industry replying to the debate, referring to the Mover of the Resolution and the points that he raised, said that there was an element of parochialism inherent in them. Here I must apologise to hon. Members; if any Member speaking on this Resolution takes the liberty of particularly referring to certain areas which he has got the liberty to represent because he comes from a certain State and is represented in the House as such, and represents the difficulties encountered by that particular State, and it that is to be termed parochialism, we will be the first people to be proud of that parochialism.

If you see the whole picture of the country, a feature of the implementation of the First and Second Five Year Plans is that industrial development, especially the basic industries and industries having a high employment potential, has shown a tendency to be concentrated in certain particular places. So also the development of the roads, the railways and the ports has shown a peculiar tendency to revolve round certain areas.

I was reminded of a story in wartime. When Belgium was occupied by the Nazi forces and half of France was yet to be occupied, a private transport company started running a few buses to Bordeaux. They wanted to get passengers for the buses going to Bordeaux. So they found out a method of advertisement. They sent out soothsayers to Belgium to tell people about where they could find their relatives who had been evacuated to France. Then they manufactured a map. Behind Bordeaux, there was kept a piece of magnet, and a pendulum used to oscillate on the map. Everybody was shown the pendulum and told that at the place on the map where the pendulum stopped oscillating, he would find his relatives. Invariably, the pendulum stopped at Bordeaux. So these people began to go to Bordeaux! Therefore, the transport company got passengers to go to Bordeaux in their buses.

Likewise, whenever a particular industry is to be located somewhere, all sorts of excuses are made out, for example, technical advice, technical report, Planning Commission's consideration, Government consideration and other considerations. Finally, when that industry has to be located, it takes a particular turn and it goes to a particular place. We are not grudging that a particular State or a particular place gets that industry because we want every part of the country to develop and within the limited resources of the Plan. But, if people become so blind that certain portions of the country and certain States are altogether completely under-developed and these industries are concentrated in certain particular places, certainly, there is objectively and subjectively also discontent and

that discontent will have to be avoided in the Third Five Year Plan.

Also the special problems facing the States will have to be looked into. Because of the limited time I will refer only to my State, how my State has been treated in both the First Five Year Plan and in the Second Five Year Plan and how the state of affairs are there today and how the State is going to get treatment in the Third Five Year Plan.

When in the Second Five Year Plan and in the First Five Year Plan so many industries have grown up in India, in my State, where the unemployment situation is the worst compared to the other States, we have got only two industries in the public sector. That is what the statistics show. One is the Hindustan Insecticides Factory employing a maximum of 130 people; and the second is the Indian Rare Earth Factory which had been started before the First Plan and which employs only 77 people. The hon. Labour Minister knows this because they are retrenched. This is the total achievement of the State of Kerala in the public sector in the two Five Year Plans.

If we talk about the big steel plants, the argument immediately comes that a steel plant cannot be started in the south because we have no iron ore or coal there. That argument sometimes stands good. But, what about the other industries?

I will come to a particular question because that question has been answered by the hon. Minister of Transport and Communications and the whole burden has been shifted to the Planning Commission today I will tell this House what is the story behind the Second Ship-building yard. The British Technical Mission came; it went and toured the country and went to 6 or 7 places to enquire about the soil and other conditions also. They made a categorical recommendation that Cochin is most suitable for the Second Ship-building yard. It took 1½ years to consider that report. And, again a committee of Government Secretaries was appointed to go into the question and they also made a recommendation that the Second Ship-building yard should be started there.

From 1957 onwards the answer given by the Ministers in this Parliament was on the assumption that in the Second Five Year Plan we are going to start the second Ship-building yard there. But nobody knows how the whole thing has faded out; and now there is no possibility of the second ship-building yard taking shape when the Third Year Plan is out.

I am not saying that because those people do not want the second ship-building yard to be located there that they are doing this. There may be different reasons. Unfortunately, when these different reasons are coming, Cochin is going to lose the second ship-building yard.

The Transport and Communications Minister says that he is prepared to include it in the Third Plan but it is for the Planning Commission. I do not know what will come out of the Planning Commission's deliberations. But, we are not at all hopeful, when we see what is gathering up in the horizon against the second ship-building yard, that Cochin is going to get it in the Third Five Year Plan because forces are working against it.

I will put forward another example. It is not prejudicial to any other State. I am only pointing this out that whenever money is invested in a particular project, first of all, the Planning Commission and the Government should see where that money could be profitably invested; and, secondly, which part of the country requires development.

When the Second Five Year Plan was taken and when the allocations for major ports are taken, it is so surprising that Cochin, which is one of the major ports in the country and

[Shri Narayanankutty Menon]

which requires development because it is in the international maritime route, and which, even from 1936 onwards, wanted a large amount of money got hardly Rs. 2 crores, while other ports, which are not actually working, got to the tune of Rs. 17 crores.

I am referring to the port of Kandla. I am not at all grudging that Gujarat should have a port; but, with all this technical advice there, the Kandla port is not working. From the last year's report I see that Kandla port shows a few thousand tons of imports. When I looked into the details the imports were all the machinery for the port itself. But the port is silted. Therefore, whenever these allocations are made, the special situation in a particular State or region is never taken into consideration. We find in certain cases deliberately certain amounts are allotted. When the Third Plan is formulated, if Kerala cannot have a steel plant, it can produce electricity very cheap and more money should be given to develop the water power. If there is not this water power, no basic industries can be started there. While formulating the Third Plan, whatever injustice has been done during the First and the Second Plans should be removed and allocations should be made suited to the natural resources of each State. As the Third Plan is in the formulating stage, I hope it would be possible for the hon. Minister to keep sufficient watch of the undeveloped areas at the cost of which over-development had taken place in certain places during the First and the Second Plans.

**श्री मू० चं० जैन** : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने दोस्त श्री द्विवेदी के प्रस्ताव की पुरजोर हिमायत करने के लिये खड़ा हुआ हूं, और हाउस के सामने इस प्रस्ताव को लाने के लिये उन को बधाई देता हूं। जो बात इस प्रस्ताव में कही गई है, मेरे ख्याल में, उस को तसलीम करने में प्लानिंग मिनिस्टर साहब को कोई इन्कार नहीं होगा। सैकिंड फाइव इअर प्लान में भी इस बात को माना गया है और अब तीसरी प्लान बन रही है। लेकिन उन को भी छोड़िये। कांग्रेस की प्लानिंग सब-कमेटी न भी इस चीज को तसलीम किया है। उस ने अपनी रिपोर्ट के पैरा ४० में यह लिखा है :

"There is lastly the question of providing for the correct regional balance in our development. While this has been accepted in principle, it will need greater emphasis in actual implementation during the Third Plan period."

इस देश का विकास ठीक प्रोपोरशन से नहीं हो रहा है इस बात को तो सब कोई जानता है। मैं ने द्विवेदी जी को बधाई इसलिये दी है कि वह यह प्रस्ताव ठीक उस समय लाये हैं जबकि हमारी तीसरी योजना बन रही है। जिस जोश के साथ द्विवेदी जी ने इस प्रस्ताव पर अपनी तकरीर की है उस से जाहिर होता है कि उन के इस प्रस्ताव के पीछे कितना जज्बा है। मैं समझता हूं कि नन्दा साहब इस की कद्र करेंगे और इस प्रस्ताव की तरफ सही तौर पर ध्यान देंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जोश इतनी जल्दी सर्द हो गया। वह तो कहीं चले भी गये।

**श्री मू० चं० जैन** : मैं ने इस प्रस्ताव पर कुछ तरमीमें दी थीं। गो आप ने उन को आउट आफ आर्डर करार दे दिया, लेकिन एक चीज आप भी तसलीम करेंगे कि जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं उन्हीं में ज्यादातर हमारे शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं, और हाउस के माननीय सदस्य भी इस बात को तसलीम करेंगे कि हमारे शिड्यूल्ड कास्ट वाले ज्यादातर उस एरिया में ही कंसेंट्रेटेड हैं जोकि विकास के लिहाज से

बैकवर्ड एरिया है । यह चीज देहाती रकबों पर भी लागू हो सकती है । आप गांवों को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं । गांवों के चारों तरफ जो आबादी होती है वह ज्यादातर हरिजनों की होती है । उन को पुश्तों से गांव के कम विकसित हिस्से में रखा गया है । तो इस को भी देखते हुए मेरी तरमीम इस प्रस्ताव के क्षेत्र के अन्दर आ सकती है । मैं इन लोगों के विकास के खयाल से ही इस पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं । मुझे विश्वास है कि जो चीजें मैं कह रहा हूं वह पहले से मिनिस्टर साहब के सामने हैं लेकिन फिर भी मैं इन चीजों पर इसलिये जोर देना चाहता हूं कि हम को आजाद हुए १२–१४ साल हो गये और हम ने पहली योजना में २२००-२३०० करोड़ रुपया खर्च किया और दूसरी योजना में ४३०० या ४५०० करोड़ खर्च कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जहां तक इन ३० फीसदी हरिजनों का सवाल है जिन को आप लेंडलेस लेबरर कह सकते हैं इन का सुधार नहीं हुआ है . . . .

**उपाध्यक्ष महोदय** : होम मिनिस्ट्री के डिमांड खत्म हो चुके, फिर भी आप इसी बात को कह रहे हैं ।

**श्री मू० चं० जैन** : अगर जो मैं ने ३० पर सेंट अबादी का जिक्र किया इसलिये आप इसको रूल आउट करते हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग इन एरियाज में रहते हैं उनके लिए हमने जो कुछ किया है वह नाकाफ़ी है । मुझे कल यह सुनकर ताज्जुब हुआ जब दातार साहब ने यह कहा कि यह कहना ग़लत है कि इन लोगों के लिए बहुत कम काम किया गया है । उन्होंने कहा कि हम भंगियों के सुधार पर ६लाख रुपया सालाना खर्च कर रहे हैं । आप देखें कि हिन्दुस्तान में कितने भंगी हैं और गवर्नमेंट उनके सुधार के लिए सिर्फ ६ लाख रुपया सालाना खर्च कर रही है । मैं कहना चाहता हूं कि यह मैंटेलिटी सही नहीं है कि हम उनके लिए काफ़ी खर्च कर रहे हैं । जो गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के मिनिस्टर यहां बैठे हैं अगर वह यह समझते हैं कि इन लोगों के लिए जो लाखों रुपया हम खर्च कर रहे हैं वह काफ़ी है, तो उनका यह सोचना गलत है । मैं इसलिए इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जो कुछ हमने उनके लिए किया है वह काफ़ी नहीं है । और हमको आयन्दा ज्यादा करना चाहिए । मैं ने दातार साहब की बातें नोट कर ली हैं । अगर वह यह कहते कि जितना हमको करना चाहिए उतना हम नहीं कर सके और हमको ज्यादा करना चाहिए था तो मुझे तसल्ली होती । लेकिन वह कहते हैं कि हम काफ़ी कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स हमारे साथ कोपरेट कर रही हैं । लेकिन हमारे पन्त साहब ने कहा कि पिछले साल भी उन्होंने चीफ़ मिनिस्टरों से इस बारे में कहा और इस साल भी जनवरी फ़रवरी में स्टेट मिनिस्टरों से कहा कि पिछड़े लोगों के लिए जो ९० लाख रुपया रखा गया था उसमें से ४५ लाख अभी खर्च नहीं हुआ । मेरी समझ में नहीं आता कि इस हालत में यह कैसे कहा जा सकता है कि हम इनके लिए काफ़ी कर रहे हैं । ४५०० करोड़ की योजना में से इनके लिए केवल ९० लाख रुपया रखा गया और वह भी खर्च नहीं होता । यह मैंटेलिटी है कि जो रुपया दिया जाता है वह ठीक तरीक़े से खर्च नहीं होता । इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं ।

वैसे तो किसी भी देश की तरक्की के लिए यह जरूरी है कि उसके हर इलाके के बसने वालों की बराबर तरक्की होती चले लेकिन मैं जानता हूं कि पांचों उंगलियां तो परमात्मा ने भी बराबर नहीं बनायीं । लेकिन उनमें कोई एक एक गज का फ़र्क़ नहीं है, मामूली फ़र्क़ है । इतना फ़र्क़ तो इन्सान की मेहनत से भी हो सकता है । लेकिन हमारे देश के सामाजिक ढांचे में लोगों में बहुत ज्यादा विषमता है । इसको दूर करना चाहिए क्योंकि इसको

[श्री मू० चं० जैन]

दूर किए बिना देश का इमोशनल इंटीग्रेशन नहीं हो सकता । हमको सोशल और इकानामिक दोनों तरह की विषमता को दूर करना होगा । मैं आप को एक खेत की मिसाल देना चाहता हूं । एक ऐसा खेत है जिसमें कि टीले हैं और गड्ढे हैं । ऐसी ही हालत हमारे समाज की है । अगर खेत को ठीक बनाना है तो आपको टीलों को काट कर गड्ढों में डालकर खेत को हमवार करना होगा । इसी तरह से आप समाज को देखें । यहां यह हाल है कि ऐसे भी इलाके हैं जहां पचासों कारखाने चल रहे हैं और दूसरी तरफ़ यह हालत है कि लोग काम के बग़ैर भूखे मर रहे हैं । ऐसा देश कैसे तरक्की कर सकता है और ऐसी हालत में कैसे लोगों में इमोशनल इंटीग्रेशन हो सकता है । कैसे लोगों में एकता हो सकती है किसी किसी खास खतरे का मुकाबला करने के लिए। तो यह ज़रूरी है कि हम उन एरियाज की तरफ़ ज्यादा ध्यान दें जिनका विकास नहीं हुआ है और उनके लिए प्लान में ज्यादा रुपया रखा जाय । और पिछड़े हुए लोगों के लिए जो रुपया रखा जाता है उसको ठीक ढंग से खर्च किया जाना चाहिए और जिस तरीके से उनका ज्यादा फ़ायदा हो सके उस तरह उसको खर्च करना चाहिए । और जिन अफ़सरों पर यह रुपया खर्च करने की जिम्मेदारी है, अगर वह उसको ठीक तरह से खर्च न कर सकें तो उसकी जांच करने के लिए आप कमेटी वग़ैरह मुकर्रर करें । हमें यह देखना चाहिए कि जो रुपया उनके लिए रखा गया है वह ठीक से खर्च होता है, और तभी उनको तसल्ली होगी ।

**17.36 hrs.**

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

मैं अब एक मिनट में अपने इलाके के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं जो कि पंजाब का हरियाना का इलाका है । इसकी तरफ़ मेरे मुअज्जिज दोस्त ने इशारा भी किया है इस इलाके की तरफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी लापरवाही रही है और पंजाब सरकार की तरफ़ से भी लापरवाही रही है । वेस्टर्न जमुना केनाल का सवाल है । उसको एक्सटेंड करना है । (कुछ आवाज़ें) जब मैं हरियाना का जिक्र करता हूं तो पंजाब के दूसरे इलाके के भाइयों को न मालूम क्यों गुस्सा आ जाता है । यह मेरे इलाके की तरक्की का सवाल है । जिस इलाके में पैदा हुआ हूं और जहां में मैं मरूंगा उस इलाके को मैं कैसे भूल सकता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह से उस इलाके को नजर अन्दाज किया गया है । जहां तक रेलों का सवाल है, उस में हम पीछे हैं । पोस्टल सर्विसिज में भी हम पीछे हैं और इंडस्ट्रीज में भी पीछे हैं । जहां तक टेक्निकल एजूकेशन का ताल्लुक है, सारे के सारे हरियाना में सिर्फ एक वेटेरिनरी कालेज है । उस को छोड़ कर और कोई टेक्निकल एजूकेशन के मुताल्लिक कालेज हमारे यहां नहीं है । टेक्निकल कालेज हमारे यहां आसानी के बन सकता था, लेकिन उस को उठा कर लुधियाना में ले जाया गया । मेरे पास टाइम की कमी है वर्ना में इस सिलसिले में और भी डीटेल्ज पेश करता । मैंने इरिगेशन मिनिस्टर को लिखा कि फाइव यीअर प्लान पीरियड के लिए जो रुपया मन्जूर किया गया, उस में से हमारे इलाके का जो हिस्सा था, उस को खर्च नहीं किया गया । वैस्टर्न जमुन कैनाल के एक्सटेंशन के लिए साठ, सत्तर, अस्सी लाख रुपया रखा गया था, लेकिन उस में से मुश्किल से पच्चीस लाख रुपया खर्च किया गया । इस के जवाब में इरीगेशन मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह तो आप की स्टेट का काम है । अभी हाल ही में मेरे

मोअ्राजिज दोस्त पंडित ठाकुर दास भार्गव ने फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर बोलते हुए कहा था कि सैंट्रल गवर्नमेंट की फेल्योर इस बात की है कि वह स्टेट गवर्नमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती है। वह यह कहती है कि हम क्या करें, यह तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हाउस को इस जवाब से कोई तसल्ली नहीं है। गवर्नमेंट चाहे कास्टीच्यूशन को अमेंड करे और चाहे कोई और तरीका अख्तियार करे, लेकिन इस मसले का हल निहायत जरूरी है। यह फेडरेल गवर्नमेंट है, यह मैं जानता हूं, लेकिन यह फ़ैक्ट है कि प्लानिंग कमीशन सब को कंट्रोल करता है। गर्नमेंट उस सूबे को ग्रान्ट देना बन्द कर दे, जो कि उस की बात को नहीं मानता है। गवर्नमेंट कोई भी कदम उठाए, लेकिन यह मुनासिब नहीं है कि यहां पर कोई मिनिस्टर खड़ा हो कर यह कहे कि हम क्या करें, जिस्ट्स बनी हुई हैं और यह तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। जब गवर्नमेंट इस मसले पर गौर करेगी और मुनासिब कार्रवाई करेगी, तो फूड की प्राडक्शन बढ़ेगी, पसमांदा इलाकों और पसमांदा लोगों की तरक्की होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपने दोस्त के प्रस्ताव की हिमायत करता हूं

**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : अध्यक्ष जी, दुख है कि प्रस्तावक महोदय यह प्रस्ताव पेश करने के बाद सदन के बाहर चले गए। शायद प्रस्ताव की कोई कमजोरी उन्होंने महसूस की हो, लेकिन उन का प्रस्ताव बड़ा आम है। जहां तक कागजों का सम्बन्ध है, किताबों का सम्बन्ध है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, मिनिस्ट्री की पालिसी का सम्बन्ध है, यह कहा जाता है कि बैकवर्ड एरियाज को प्रोत्साहन दिया जाये और उन को व्यवसाय दिया जाये, ताकि हमारे देश में जो असमानता है-धनी और गरीब में जो असमानता पढ़े लिखे और बेपढ़े-लिखे में जो असमानता है, दवा खाकर पचाने वाले और अन्न पचाने के लिए जिस के पेट में न हो, उन में जो असमानता है- उस को यथा-सम्भव कम किया जाये। लेकिन जब इस नीति को कार्य रूप में परिणित करने की बात आती है, तो गाड़ी वहां ही रूक जाती है। अभी बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े कल-कारखानों के लिए, चाहे जिस नाम पर हो, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन पिछड़े एरियाज में रोजगार-धंधे देने के लिए हमारी सरकार, प्लानिंग कमीशन और सब ने मिल कर तीन करोड़ कई लाख रुपए का आयोजन किया था और उस में से शायद दो करोड़ ही अभी दे पाए हैं और बाकी पड़ा हुआ है। बंट भी नहीं सकता और काम भी नहीं होता है। अगर हम कागज को देखें, तो हम पढ़ेंगे कि देहात और खेती की तरक्की के लिए सब कुछ किया जाये। मेरा कहना यह है कि अगर हमारी वानी और कर्त्तव्य दोनों साथ चलें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आज देहातों की हालत करीब करीब वही है, जो आज से दस बरस पहले थी, जहां कहीं पानी चला गया है, नल-कूप बन गया है, वहां कुछ तरक्की हो गई है, लेकिन आज देहात की जनता, जो पिछड़े इलाके कहलाते हैं, उन की जनता यह महसूस नहीं करती कि ब्रिटिश राज और इस राज में कोई अन्तर है। उन के सामने शासन वही है।

**श्री विभूति मिश्र** : वे ब्रिटिश राज और इस राज में बहुत अन्तर करते हैं।

**श्री सिंहासन सिंह** : कागज पर अन्तर करते हैं। उन के सामने पुलिस वही है, और चीजें वहीं हैं। जब उन को पानी मिलता है, बिजली मिलती है, तो वे अन्तर करते हैं, लेकिन अपने प्रति व्यवहार में, अपने प्रति रुझान में वे कोई अन्तर नहीं अनुभव करते। माननीय सदस्य के यहां तम्बाकू पैदा होता है। धन हो गया है, इस लिए वे शायद अन्तर अनुभव करते हैं, लेकिन और जगह लोग अन्तर अनुभव नहीं करते। पिछड़े इलाके के क्या मायने हैं? पिछड़ा इलाका किस को कहते हैं?

[श्री सिंहासन सिंह]

पिछड़ा इलाका वह हो सकता है कि जहां रास्ता नहीं है, क्योंकि किसी देश की तरक्की के लिए तीन चीजों की ग्रावश्यकता है: पहुंचने के लिए सुगम रास्ते हों, सब के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो ग्रौर पीने ग्रौर खेती का काम करने के लिए पानी मिले । ग्रगर इन तीन चीज़ों की–कम्यूनिकेशन, एजुकेशन ग्रौर इर्रिगेशन की-व्यवस्था हो जाये, तो हमारे सब मसले हल हो सकते हैं । इस लिए हम को पिछड़े इलाके को इस नाप से नापना चाहिए कि वहां रास्ते हैं या नहीं, शिक्षा का प्रचार है या नहीं ग्रौर उन के लिए पानी की व्यवस्था है या नहीं । ग्राप ने पेपर में देखा होगा कि पंजाब में किसी जगह पीने के लिए पानी नहीं है ग्रौर वहां के लिए इन्तज़ाम हो रहा है । नागपुर प्लान के ग्रनुसार देश भर में सड़कें तैयार करने का विचार किया गया था । सड़कें तैयार हो रही हैं, सीमेंट ग्रौर तारकोल की सड़कें बनती हैं, लेकिन कच्ची सड़कों के साथ उन को मिलाने के सम्बन्ध में बहुत कम इन्तज़ाम हो रहा है । देहात में ग्राने जाने के लिए रास्ते कम हैं, इस लिए ब्लाक डेवेलपमेंट की जो गाड़ियां देहात में जाती हैं, वे सिर्फ़ वहीं पहुंचती हैं, जहां सड़कें हैं । दूसरी जगह वे नहीं पहुंच पाती हैं । पहला काम यह होना चाहिए कि गांव गांव को ग्रापस में मिलाने की स्कीम बनाई जाये, ऐसे रास्ते बनाए जायें, जिन पर बैल-गाड़ी ग्रौर मोटर सब चलें । ग्रगर इस तरफ़ ध्यान गया भी तो हम हमेशा यह देखते हैं कि हमारी मोटर गाड़ी से जो गर्द उड़ती है, हव मह पर न पड़े, इस लिए वहां सीमेंट ग्रौर तारकोल की सड़क बना दी जाये, यह विचार सामने होता है । वह ठीक है । वह करें, लेकिन तारकोल ग्रौर सीमेंट की सड़क जब बनाते हैं, तो उस के साथ साथ यह भी ग्रावश्यक है कि हर जगह, जहां जहां ज़रूरत हो, वहां सड़कें बना दी जायें, चाहे वे कच्ची हों । कल एक भाई ने कहा कि उन को सड़कें नहीं बन रही हैं, क्योंकि वे कच्ची होंगी पक्की सड़क जहां है, वहां है लेकिन कच्ची नहीं बनती तो कच्ची होने के कारण ग्रागे नहीं बढ़ सकते । इस लिए नीचे ही तरक्की रह जाती, क्योंकि जहां सड़कें हैं गाड़ियां हैं वहां सब प्रकार की तरक्की होती है, बिजली वगैरह की तरक्की होती र । सरकार भी कहती है कि तुम्हारे यहा रास्ता नहीं है, कैसे जायें ? यही तो हमारी मांग है कि वहां राहता बनाया जाये, ताकि वहां पहुंच सकें–पिछड़े इलाकों को तरक्की देने के लिए रास्ता बनाया जाये । सरकार कहती है कि तुम्हारे यहां बिजली नहीं है, इस लिए छोटे काम-धंधे नहीं हो सकते हैं । बिजली सरकार बनायेगी नहीं ग्रौर हम बिजली रख नहीं सकते, बिजली बनाने की ताकत हमारे पास नहीं है । सरकार कह सकती है कि बिजली बम्बई, कलकत्ते में है, इस लिए वहां रेल-गाड़ी बिजली से चलेगी, सब कुछ काम बिजली से होगा, लेकिन जहां बिजली नहीं है, वहां कोई व्यवस्था नहीं की जायगी । ग्रगर व्यवस्था करें, तो तरक्की हो सकती है । ग्रसली बात यह है कि सरकार की मनोवृत्ति में परिवर्तन हो । वह परिवर्तन कैसा हो ? काग़ज़ में सरकार देहात की तरफ़ जाती है । हर एक ग्रादमी कहता है कि देहात की तरफ़ चलो । गांधी जी कहा करते थे कि देहात की तरफ़ चलो, लेकिन टाल किधर है ? शहरों की तरफ़ चलों । हर तरफ़ शहरों की ग्राबादी बढ़ रही है ग्रौर देहात की ग्राबादी घट रही है । क्या सरकार ने कभी इस कारण विचारा ? प्लानिंग मिनिस्टर मुझे माफ़ करेंगे यदि मैं यह कहूं कि हमारे देश का प्लान ग्रनप्लान्ड हो गया है । ग्राज देहात का जीवन महंगा है ग्रौर शहर का जीवन सस्ता है । शहर में सिवाये मकान की दिक्कत के ग्रौर सब चीज़ें सुलभ हैं ग्रौर देहात में वही चीज़ें दुर्लभ हैं, नहीं मिल सकती हैं । ग्राज हमारी ऐसी इकानोमी हो गई है कि यद्यपि गेहूं देहात में पैदा होता है, लेकिन वहां वह महंगा बिकता है ग्रौर शहर में सस्ता बिकता है ।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : हमारे यहां है ।

**श्री सिंहासन सिंह** : इन के यहां इस लिए है कि इन के यहां बीस मील पर बाजार है, पहुंच नहीं पाता है, लेकिन जहां थोड़ा बहुत पहुंच पाता है, वह देहात में जा कर महंगा बिकता है, क्योंकि शहर के बनिए खरीद लेते हैं और जब हम को जरूरत पड़ती है, तो हम को महंगा पड़ता है । आप देहात में किसी जगह चले जायें । हमारे यहां गोरखपुर में देहात में गेहूं बीस, बाइस रुपए मन मिलता है और हापुड़ में अठारह रुपए मन मिलता है । चला आता है घूम फिर कर । जो ज़िले ज़िले की रोक-थाम कर ली गई है, उस से चलता तो है ही, लेकिन प्रतिकर देने की वजह से और महंगा पड़ता है । देहात से लोग शहरों की तरफ़ आते हैं, क्योंकि व्यवसाय शहरों में हैं । उन को वहां काम मिलता है । अगर कुछ और न मिला तो रिक्षा ही चलाने को मिल जाता है । लोगों को शहरों से देहात की तरफ़ लाने के लिये यह ज़रूरी है कि हम उन को देहात की तरफ़ आकर्षित करें । आकर्षण यह है कि देहात में भी सड़क हो, तो जिन को कोई काम न मिले, वे वहां पर भी रिक्षा चला सकते हैं । देहात में जहां जहां पक्की सड़कें हैं, वहां लोग रिक्षा चलाते हैं और कुछ न कुछ कमा लेते हैं । वहां ऐसी सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण लोगों को दिक्कत होती है । जरूरत इस बात की है कि देहात के प्रति सरकार की मनोवृत्ति बदले, क्योंकि सारा हिन्दुस्तान देहात में बसता है । रूरल एन्क्वायरी कमेटी ने भी कहा है कि देश के ७५ फ़ीसदी आदमी तो देहात में बस कर खेती करते हैं । उन की ओर सरकार का रुझान नहीं है । एक वेयरहाउसिंग का ऑरेगन बनाया गया, लेकिन उस की बिल्डिंग शहर में बन रही है । अगर वह देहात में बनती, तो हम देहात में अपना गल्ला जमा करते और वहां पर सड़क बनती, लेकिन वह बिल्डिंग भी शहर में बन रही है । कागज़ पर बात की जाती है देहात और बैकवर्ड एरियाज़ की तरक्की की, लेकिन काम सारा बड़े बड़े शहरों में होता है ।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यह बहुत ज़रूरी है । थर्ड फाइव यीअर प्लान आ रहा है । उस में हमारी एक योजना यह है कि हम देश की बेकारी को दूर करें । वाजियाना तभी सफल हो सकती है कि जहां अधिक से अधिक आदमी बसते हैं, उन को वहीं काम दिया जाये, ताकि उन को दूर न जा कर वहीं काम मिल जाये और वहीं उन की बेकारी दूर हो जाय व और अपना माल पैदा कर के जहां तक हो सके, स्वत: खत्म करें और उस के बाद बाहर भेजें । विनोबा भावे के ग्राम-राज का नारा लगाया है । उन की इच्छा है कि हर एक ग्राम संतुलित रहे और अपनी चीज़ें वह स्वयं मुहैया कर सके और जो बचें, वे बाहर जायें । ग्राम-राज लाने के लिये यह ज़रूरी है कि सरकार उस तरफ़ कदम बढ़ाये और ग्रामों की तरफ़ ध्यान दे और कागज़ पर जो है, उस को साकार रूप दे ।

अभी मेहता कमेटी की रिपोर्ट निकली थी कि ब्लाक डिवेलेपमेंट लेवेल पर हम अपने अधिकार को अलग अलग करें । कुछ साथियों ने कहा कि इस के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है । मैं भी समझता हूं कि इस के बारे में आप ने कुछ नहीं किया है । आज सारे अधिकार जो ज़िला कलैक्टर के हाथ में रख दिये गये हैं । अंग्रेज़ों के ज़माने में वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहलाता था या कलैक्टर कहलाता था और हमारे ज़माने में वह जिलाधीश हो गया है, जिले का अधीश । जो दूसरे धीश थे, वह बड़े बड़े धीश थे, वे तो मिट गये लेकिन यहां हम ने जिलाधीश बना दिये हैं । नतीजा यह है कि वह जिले का मालिक हो गया है । उस के दिल में आता है तो काम करता है और अगर नहीं आता है तो नहीं करता है ।

[श्री सिंहासन सिंह]

आप ने एडवाइज़री कमेटीज़ भी बना रखी हैं लेकिन उन से भी कोई लाभ नहीं होता है ।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : दफ्तर भी घर पर ही करता है ।

**श्री सिंहासन सिंह** : लड़ाई के ज़माने में कलैक्टर कम से कम कचहरी तो करता था लेकिन अब कोई जिलाधीश कचहरी नहीं करता है । वह जिलाधीश है, सेवक नहीं है । घर बैठ कर दफ्तर करता है । जिन के ज़रिये आज हम कार्य करते हैं, उन की यह हालत है । वह महलों में रह कर ही इंटरव्यूज़ ग्रान्ट करता है और दिन भर इंटरव्यू ग्रांट करने के सिवा और काम उस का नहीं रह गया है । उसी को सब अधिकार दे दिये गये हैं ।

मैं अन्त में माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि कहने के बजाय डिसिप्लिंड लाइफ लीड कर के लोगों को यह चीज़ दिखाई जानी चाहिये ।

**Mr. Speaker:** Shri M. R. Krishna.

**Shri Braj Raj Singh** *rose*—

**Mr. Speaker:** I will call him after Shri Krishna.

**Shri M. R. Krishna** (Karimnagar—Reserved Sch. Castes): Only this morning we heard the Home Minister giving certain assurances and hopes to the Backward Classes.

**An Hon. Member:** Backward areas.

**Shri M. R. Krishna:** Now we are discussing about the backward areas.

**Shri S. M. Banerjee:** Yes, backward classes in backward areas.

**Shri M. R. Krishna:** As you know, Sir, I come from a State in which the Chief Minister is also from a backward class; the State is also backward, and that is Andhra Pradesh. My hon. friends, who have spoken just before me, have given various reasons to point out the defects of the Planning Commission in setting up industries in various places, ignoring the areas which are very much under-developed.

There are various instances. If one has to quote the industries in America, England and other places, I think ten minutes will not be sufficient. Therefore I would like to confine my remarks only to certain things which are prevalent in this country.

The Planning Commission says that wherever the industries have to be located in the public sector they are very strict about raw material, the cost of production and so on. In places where they want to encourage private industries they want the private people to come forward with lot of money in a backward area. I do not know whether the Planning Commission members know very well the conditions in the backward areas and rich people in backward areas. Had they only known about it I do not think they would have put this condition as one of the very important conditions for locating private or public industries in the backward areas.

I think the Planning Commission is moving in the direction only to help those people who are very rich. For instance, in Andhra Pradesh a factory was to be located. For that the Andhra Pradesh Government was trying to find out people or private firms who could come forward to invest their money. Many people from other parts, like Bombay, have come forward to help the industry but on the condition that the industry should be located in Bombay. Therefore it becomes impossible for any State, however honest the State or the people might be, to get that private participation in order to get some industries.

I was speaking about the Heavy Forging and and Structural Steel Factory which was to be located in Andhra Pradesh and for which the Andhra Pradesh Government is still struggling. The Telangana part of Andhra Pradesh, as it is known to this House, is very backward not industrially but even in the agricultural field compared to the Andhra areas, the Telangana part is very backward and the people are very backward. Most of the areas there are barren and there are no river valley projects there. They will have to depend still on agriculture.

The former Government, that is, the Hyderabad Government had certain plans. Regarding those plans the people of that State thought that when this integration takes place the Andhra Pradesh Government will be assisted to start those industries. But to our misfortune all those promises and the industries which were to come up have now been thrown into cold storage. Again the same principle has been applied even there, namely, that if people are willing to come forward to invest their money then only they will be able to get the industries.

Even Ordnance Depots and other offices have been shifted out of Andhra Pradesh—I mean Hyderabad and other places. Formerly buildings had been constructed to locate certain depots because in Defence particular type of accommodation is required to locate the Ordnance depots and other things. Even those places have been vacated and they have been shifted to other areas.

Now some places, like Bombay and other places, have got lot of industries even after the withdrawal of the British. The British also wanted to develop only those areas and that is the way in which our Government is also trying to develop these areas. All the industries are concentrated in these places. For instance, even the Railway offices have been shifted from Hyderabad to Bombay. Therefore the people in these areas feel very bad because of the half-hearted way in which Government is trying to develop the backward areas.

I had to voice the feeling of Andhra Pradesh here because recently in the Andhra Pradesh Assembly members have taken a decision that they should have a special session of the Assembly to voice their feelings. Every Minister, the Chief Minister and the Government of Andhra Pradesh have tried to convince the Central Government about the backwardness of that State. And they got assurances, but the Central Government never try to honour their commitments. That is why I feel it my duty to express here the feelings of the people of Andhra Pradesh before the Andhra Pradesh Assembly itself passes any resolutions on these lines. The Minister for Labour in the Andhra Pradesh Government—just as our Nandaji here—is even assuring the people through the Assembly that he is going to start one of the first institutions there to train people to work on safety methods, provide for health, welfare and other things. The Labour Minister there said that an Industrial Safety Protective Institute is going to be started in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh comes forward to do many things without knowing that the Central Government is not going to uitilse their services!

Once the Central Government wanted to manufacture diesel as well as ordinary railway coaches in one of the factories in Hyderabad. We thought that it was coming up and that orders would be coming to that factory. But suddenly it has been taken over to Calcutta and other places, even though this factory is very well equipped to produce this kind of things. At the Bangalore and Perambur workshops these things have now been produced. Even though the Bangalore workshop is already working to its full capacity,

[Shri M. R. Krishna]

yet the Railway Ministry has given various orders to them. The result was that the factories which are very well equipped in Andhra Pradesh have not been encouraged to do this kind of things.

Again, the Aircraft factory is one of the things which the Andhra Pradesh Government wanted to proceed with, for which the America have already got plans and everything else. American collaborators are offering help. But the Planning Commission and the Government of India want to consult various other agencies and thereby the things are very much delayed.

It is true that Andhra Pradesh is an agricultural State, but that does not mean that the entire Andhra Pradesh is depending on agriculture and their income is derived only from agriculture. As I stated earlier, the Telengana part of Andhra Pradesh is barren. Without irrigation facilities they will not be able to produce anything. So it is only industry which could help them to come up.

When the Government of India feels that backward areas should be developed and should be encouraged, I do not see any reason why in the matter of Andhra Pradesh proper treatment is not meted out to it. In the National Development Council, every time, right from the time when Shri Ramakrishna Rao was the Chief Minister of Hyderabad, from the time till the recent Conference of the Chief Ministers, assurances have been given. The Chief Ministers coming from the State have tried to explain to the Government of India and insisted on the need for industries. But yet their voice is not at all felt and Andhra Pradesh is in the same state as it was.

I have got figures here to show the way in which the various other States have been helped in the matter of having Central industries in the public sector. A number of other ancillary industries have developed there as a result of the principal industries; other social welfare measures, communications and various other things have also developed as a result of one industry being located.

**18 hrs.**

If you go into the history as to how these industries have been started in some places, you will find that the Britishers wanted to industrialise the ports, and they did it. But now, after independence, some of the industries which should not be necessarily on the borders, because of certain dangers from outside, have been located there, and the Government and the Planning Commission do not seem to feel the necessity of shifting them from these places which are very near the danger zones. From the point of view of safety, many of the industries which are now being located in various places, have to be shifted to the safer zones. If there is no other consideration, the Ministry will have to give proper thought to this at least. After all, to start these industries and finance them, the Central Government will have to depend on the various States including the backward States, and though they may spend money to set up industries, they will have to take proper care to see that in a time of emergency they will be able to stand against all kinds of dangers.

Many of the industries which are now being located are not in the safer places, and the Government will have to be very careful; at least in the Third Plan when they are going to produce some of the very important things required by the country, including defence requirements, some of these industries should be shifted to the safer places, and they should definitely not be in the danger zones.

**Mr. Speaker:** Shri Braj Raj Singh.

**Shri Harish Chandra Mathur** (Pali): Sir, this resolution refers to undeveloped areas, and at least areas which are fully known as undeveloped should get some representation here.

**Some Hon. Members** *rose*—

**Mr. Speaker:** Let me have an idea as to what the under-developed areas are.

**An Hon. Member:** I represent Madhya Pradesh.

**Shri Bibhuti Mishra:** I have moved my amendment.

**Shri Ram Krishan Gupta** (Mahendragarh): I have also moved an amendment.

**Mr. Speaker:** Is Punjab also under-developed?

**Pandit Thakur Das Bhargava:** Punjab is certainly undeveloped.

**Shri Shree Narayan Das** (Darbhanga): We come from backward areas.

**Shri Kalika Singh** (Azamgarh): Eastern U.P.

**Shri Harish Chandra Mathur:** If a a gentleman has represented U.P., it is all right. One has represented Punjab. At least you should come to other places.

**Mr. Speaker:** I am coming. I will call a member from Rajasthan and also from Madhya Pradesh.

**Shri Harish Chandra Mathur:** Madhya Pradesh has already been represented by the Mover.

**Mr. Speaker:** I have called Shri Braj Raj Singh. Very well, let him go on. Anyhow, I leave it to hon. Members themselves to decide. There must be a proper adjustment. There is no opposition so far as Private Members' Bills and Resolutions are concerned, I think the opposition is only the Government. As between the various parties, I do not count any opposition, and therefore I am not going to proceed on the basis of parties here. I made a mistake in calling Shri Braj Raj Singh. Somehow it stuck in my mind that I must call groups, leaders of groups, but I will not follow that distinction hereafter. So far as Private Members' Bills and Resolutions are concerned, all are on the same footing, except the hon. Minister.

**Shri Kalika Singh:** It is a mistake in planning.

**Mr. Speaker:** Very well. The Minister also agrees.

**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो वाद-विवाद हो रहा है, और उस पर माननीय सदस्यों ने

**Shri Shree Narayan Das:** There is no quorum in the House.

**Mr. Speaker:** We do not think of quorum in the evening.

**श्री ब्रज राज सिंह** : आज माननीय सदस्यों ने जो विचार यहां पर प्रकट किये हैं उस से साफ यह पता लगता है कि कोई विशेष इलाके ऐसे नहीं हैं जोकि पिछड़े हुए हैं, बल्कि सारा मुल्क ऐसा है जो पिछड़ा हुआ है, और अगर इस में झगड़ा होने लगा कि कौन किस से ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तब फिर प्रश्न दूसरे उठ जायेंगे । इस में किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं कि मुल्क सारे का सारा पिछड़ा हुआ है, और सारे मुल्क को ऊपर उठाना है । ऐसी हालत में समस्या यह नहीं है कि कौन से पिछड़े हुए इलाके हैं और किन को पहले उठाना है बल्कि समस्या यह है कि जो कुछ सरकार की योजनायें बन रही हैं, वे ढंग से चल रही हैं या नहीं । उन में कोई मूलभूत कमियां तो इस तरह की नहीं हैं जिन की वजह से योजना को पूरा करने में दिक्कत आ रही हो, और जिन वस्तुओं का समावेश होना चाहिये वह ठीक से हो रहा है या नहीं ।

**Shri Shree Narayan Das** (Darbhanga): I rise to a point of order. There is no quorum in the House.

[Shri Shree Narayan Das]

There are not more than twenty Members in the House.

**Mr. Speaker:** We are not voting on any item now. So, let the hon. Member Shri Braj Raj Singh go on.

**श्री ब्रजराज सिंह** : अगर सवाल यह हो कि कौन से इलाके हैं जो पिछड़े हुए हैं, तब मैं निवेदन करूंगा कि आंकड़ों से यह चीज साबित की जा सकती है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन मैं उस में नहीं जाना चाहता। मैं तो यह निवेदन करना चाहता था कि सारा प्लानिंग का ढांचा इस तरह का है कि जहां पर कुछ रुपया पहले से मौजूद है, साधन पहये से मौजूद हैं, उन के साधनों को और बढ़ाने की बात चलती है और जहां पर कुछ नहीं है, उन की तरफ कोई साधन बढ़ाने की बात नहीं की जाती है। उदाहरण के लिये आप देखिये। उत्तर प्रदेश में आप ने रिहन्द बांध बनाया, वहां बिजली पैदा की। करीब १ लाख कीलोवाट से अधिक बिजली वहीं पैदा होने को है। ५५ लाख कीलोवाट बिजली तो शायद बिड़ला साहब को दी जा रही है।

**Shri Shree Narayan Das:** I rise to a point of order. I have objection.

**Mr. Speaker:** What is his objection?

**Shri Shree Narayan Das:** I pointed out to you that there was no quorum in the House, and no bell was rung, and Members have not come in, and, therefore, the proceedings of the House should not be carried on. That is the point of order.

**Shri Narayanankutty Menon:** His point of order is that there was no quorum.

**Shri S. M. Banerjee:** Previously. such questions were raised, and the Opposition Parties and all other wanted to have a convention that during the non-official business such questions should not be raised. If the hon. Member wants to speak, I shall not speak on my amendment, but let him speak. But let him not raise such questions regarding quorum.

**Shri Braj Raj Singh:** May I submit a word? If this is the way in which a Member of the ruling party is going to behave, I shall show that the proceedings of the House cannot go on any day. I can say at any time that there is no quorum.

**Mr. Speaker:** I think the whole House agreed unanimously—that during the extended period, that is, after the normal period of five o'clock, we do not insist upon a quorum, as during the lunch hour. Only, I said, the other day that no division will be taken here. Therefore, let us not insist upon it. What applies to the hon. Member on this side of the House will apply equally well to the hon. Member on the other side.

**Shri Narayanankutty Menon:** Not equally.

**Shri Shree Narayan Das:** My point of order is against no individual, and it is not against any particular party. My point of order is general namely that when sufficient number of Members are not present, the proceedings should not be carried on. On some occasion, we may not raise it, but ordinarily we should not go against the Constitution.

**Mr. Speaker:** I may point out to the hon. Member what happened the other day. Possibly, the hon. Member was not present here on that day.

On the 22nd March, 1960, the House was scheduled to sit till 6.30 p.m. After the Question Hour, when the discussion of the Demands for Grants in respect of the Ministry of Food and

Agriculture was resumed, some Members submitted that more time should be allotted to the discussion of the Demands for Grants of the Ministry of Food and Agriculture, and that for that purpose, if necessary, they were prepared to sit till 7 p.m. Thereupon, some Members expressed difficulties about continuance of quorum after 5 p.m. In this connection, I observed as follows:

"My attention has been drawn to a provision in the Standing Orders of the Central Legislative Assembly."

—that is, the rules made under the Government of India Act. 1935.

"There is the following provision there:

'Adjournment for failure of a quorum: If the President on a count being demanded by a Member at any time during a meeting ascertains that twenty-five Members (it is now 50 Members here) are not present, he shall adjourn the Assembly till the next day on which it ordinarily sits:'.

There is also a proviso which is important.

"Provided that no demand for a count to ascertain the presence of quorum shall be made within one hour of any previous count."

We have adopted one convention that during the lunch interval, nobody will demand quorum, provided, of course, the discussion goes on, but nothing is brought up for voting. For voting, quorum is necessary.

Similarly, if the House agrees, within one hour of a count having been taken, we shall not ask for quorum, except when a division has to be taken, in which case there must be quorum. That would mean, if once a count is taken, within one hour from that, once again a count shall not be taken."

When a Member (Shri Naushir Bharucha) submitted that the convention would be against the provisions of article 100 of the Constitution, I observed:

"The practice during lunch interval has been adopted so long, notwithstanding the fact that there is a provision against it in the Constitution. If that is right, this is also right. If that is wrong, both will be wrong......

Conventions are always established notwithstanding the law. There is no need for a convention if the law itself works satisfactorily. Law cannot be changed every minute, but human practice goes on changing to suit changing times. I am not introducing the practice as a rule now. It will develop as a convention, as we progress. Let us understand that if we extend the time, during the extended time, no quorum will be demanded except where it is proposed to take a division. Let it be the general understanding."

That was accepted by the whole House.

Shri Braj Raj Singh may continue.

**Shri M. L. Dwivedi:** I request that as this is a very important Resolution, the time allotted to it may be increased so that it can be discussed next time also.

**Mr. Speaker:** This will go to the next day.

**Shri M. L. Dwivedi:** The time may be extended.

**Mr. Speaker:** Let us see when we go to the next day.

**Shri M. L. Dwivedi:** Then the House may adjourn now.

**Mr. Speaker:** I am not going to adjourn the House. The hon. Member moves a Resolution. He is interested only in hearing his own

[Mr. Speaker]

voice, not of others who would like to speak. This is a rather strange request.

**Shri M. L. Dwivedi:** I am prepared to fully hear every Member.

**Mr. Speaker:** Then let him continue sitting.

**Shri Shree Narayan Das:** You have just read out the ruling you gave. I will abide by it. But was any count taken when the question of lack of quorum was raised in the House today?

**Mr. Speaker:** He did not follow the last part of what I said. I referred to the previous rules and said that ultimately whenever time is extended and the House continues sitting, no quorum will be demanded, unless a division was sought. This is the extended time—the extension of time by one more hour.

**Shri Shree Narayan Das:** I humbly submit that this is a constitutional provision regarding quorum.

**Mr. Speaker:** I have looked into all that. If only he had heard my ruling fully, he would have known that all this objection was raised by Shri Naushir Bharucha the other day. I considered this matter and said—that a convention would be established against the law—of course, not as absolutely immoral or unjustifiable. The whole House accepted it. It is not for me to go on changing the decision of the House from time to time.

**श्री ब्रजराज सिंह** : मुझे अफसोस है कि सरकारी पार्टी के लोग जिन की कि जिम्मेदारी यह है कि सदन् की कार्यवाही को चलाया जाये वे खुद इस तरह की आपत्तियां उठाते हैं जिन से कि इस सदन् की कार्यवाही चलाने में कठिनाई आती हो . . . . .

**Shri Shree Narayan Das:** On a point of personal explanation......

**Mr. Speaker:** No, no, not necessary. Let him leave it.

**Shri Shree Narayan Das:** He is throwing responsibility on the Members of the Congress Party here.

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं ने तो कहा था कि चन्द रोज हुए जब यह सवाल उठाया गया था । यह पार्टी का सवाल नहीं है .

**श्री ब्रजराज सिंह** : यह आप की जिम्मेदारी का प्रश्न है . . .

**Shri Shree Narayan Das:** I have not raised this question on behalf of the Congress or any party. It is not a party matter. Sometimes, hon. Members of the Opposition are not present in the House.

**Shri Braj Raj Singh:** The Congress Party is responsible for keeping quorum in the House. It is running the Government. It is not my responsibility.

**Shri Shree Narayan Das:** I did not raise it as a Member of the Congress Party. It is a general question. (*Interruptions.*)

**Mr. Speaker:** Order, order. Is there going to be chaos in the House? I cannot understand this kind of talk. The hon. Member may proceed. I have given my ruling. The hon. Member who raised the point has accepted it. There is no question of challenging the ruling. Only the hon. Member need not accuse them. They are entitled to raise a point—and the point is novel.

**Shri Braj Raj Singh:** I am not accusing anyone.

**Mr. Speaker:** I am really surprised at the fact only the hon. Member is there from the Opposition to speak. How is it that there are only three Members of the Opposition in the

Opposition now? He thinks it is the business of the Government to have quorum? It is the business of everybody, including the Opposition, to have quorum.

**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं निवेदन कर रहा था कि रिहैन्द डैम से बिजली पैदा की गई जिस में से कि ग्राधे से ग्रधिक बिजली एक साहब के कारखाने को दी जा रही है ग्रौर वह भी बिना हानि लाभ के ग्राधार पर दी जा रही है । जिस भाव पर बिजली पैदा होगी उसी भाव पर उन को दी जायगी । यह गलत तरीका है । इस बिजली से ग्रगर ग्राप चाहें तो सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे कारखाने खोल सकते हैं जिन से लाखों ग्रादमियों को काम मिल सकता है ग्रौर ग्राज जो उन में एक गरीबी ग्रौर बेकारी है वह दूर हो कर वे ग्रपना ग्रौर ग्रपने परिवार वालों का पेट पाल सकते हैं । इसी तरह से यह रेलों के विद्युतीकरण का सवाल है । ग्राज हम रेलों का विद्युतीकरण करने जा रहे हैं लेकिन जहां पर जरूरत इस बात की है कि ग्रधिक से ग्रधिक कारखाने खुलें, छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित हों ग्रौर लोगों को काम मिले, वह न कर के हम ऐसे काम करते चले जा रहे हैं जिस से बेकारी बढ़ती है । ग्रौद्योगीकरण ग्रधिक होता है लेकिन दूसरी तरफ गरीबी बढ़ती है । ग्रगर ग्राप पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं तो इस के लिये जो कुछ ग्राप के पास साधन हैं उन को ले कर इस तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी ग्रौर योजना बनानी पड़ेगी ताकि ग्रधिक से ग्रधिक लोगों को फायदा हो । मेरी शिकायत यह है कि सरकार इस तरह का काम नहीं कर रही है । सरकार ने यह स्टील का कारखाना खोला तो वह ग्रच्छा काम किया है ग्रौर उस से छोटे छोटे कारखाने हमारे चल सकेंगे ग्रौर उन के द्वारा लोगों को काफी तादाद में काम मिल सकेगा । भाखरा की बिजली खर्च होनी चाहिये पंजाब के गाँवों में उद्योग खोलने के लिये । लेकिन भाखरा की बिजली ग्रगर दिल्ली में ग्राये तो यह उलटा काम हो जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का सारा काम इस तरह से उल्टा चल रहा है ग्रौर जिस साधन का उपयोग होना चाहिये पिछड़े हुए लोगों के विकास के लिये वह नहीं हो पाता । इसलिये प्रश्न यह उठता है कि जब हम तीसरी पंचवार्षिक योजना को बनाने जा रहे हैं, जब यह सोचा जा रहा है कि वह योजना कैसी हो, तो सरकार को इन सब गलतियों पर ध्यान देना चाहिये । उदाहरण के लिये स्टील प्लांट एक ग्रच्छी चीज है, बिजली का बनाना एक ग्रच्छी चीज है, लेकिन हमें देखना होगा कि जो इलाके पिछड़े हुए पड़े हैं उन को बढ़ाने के लिये हम क्या साधन काम में ला रहे हैं । रेलों में हम बिजली लगाते हैं, एक पटरी की जगह दो पटरियां लगाते हैं ताकि साहब लोगों को सफर में देर न हो जाये । लेकिन जहां पर कोई ग्रावागमन के साधन नहीं हैं, वहां हम कच्ची सड़क भी बनाने के लिये तैयार नहीं हैं । ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर ने बताया कि उन्हों ने ग्रपने विभाग के लिये १००० करोड़ रुपये की योजना बनाई थी लेकिन प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि तुम को २५० करोड़ से ज्यादा नहीं मिल सकता । इस के मानी यह हैं कि कोई सड़क नहीं बन सकेगी । मैं कहना चाहूंगा कि रेलें भी बढ़ाना चाहियें । उन में बिजली भी लगाना चाहिये ग्रौर जरूरी है, हवाई जहाजों की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहियें । लेकिन हम को यह देखना यह कहिये कि हम किस चीज को प्रायरटी दें । जब रेल ग्रौर सड़क का सवाल सामने ग्राये तो जब तक पिछड़े हुए इलाकों में सड़क न बन जाये हम को रेल का बनाना बन्द रखना चाहिये । जहां तक दोहरी लाइन लगाने का सवाल है, हम को इसे उस समय तक नहीं करना चाहियें जब तक कि दूसरे स्थानों में एक लाइन न लग जाये । तो हमें इस तरह के काम बन्द कर देने चाहियें । मेरी सरकार से यही शिकायत है कि प्रायरिटी के हिसाब से काम नहीं किया जाता । जिस का जौर हो

[श्री ब्रजराज सिंह]

जाता है उस का काम चल जाता है। आप रेलों में एयरकंडीशनिंग का इन्तिजाम कर रहे हैं, हवाई जहाजों में भी बढ़ौतरी कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी इमारतें भी बन रही हैं। पर स्कूल के लिये इमारत आप नहीं बना सकते। इसलिये मेरा निवेदन है कि द्विवेदी जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सरकार पर जोर देना चाहिये कि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में वे गलतियां नहीं होनी चाहिये जो कि पहली और दूसरी योजनाओं में हुई और जिन के कारण बेकारों की फौज बढ़ती चली जा रही है। जो पिछड़े हुए इलाके हैं उन में विकास नहीं हो रहा है। यह सब काम हम को करना है। अगर द्विवेदी जी के प्रस्ताव का सरकार पर प्रभाव पड़ता है तो मैं समझता हूं कि तृतीय योजना के द्वारा हम देश में ज्यादा विकास कार्य कर सकेंगे।

अभी तक देश में ऐसे लोग नहीं थे जो कि योजना के खिलाफ हों। उनकी आप से अभी तक यही शिकायत होती थी कि आप योजना को ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं, आप को योजना पर ज्यादा रुपया खर्च करना चाहिये था। लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अब देश में ऐसे लोगों का संघ बन रहा है जो कि योजना के खिलाफ हैं और यह आप के लिये खतरे की घंटी है। यदि आप योजना को ठीक ढंग से नहीं चलाते तो आप के लिये खतरा हो सकता है क्योंकि मुल्क में ऐसे लोक पैदा हो गये हैं जो कि योजना के खिलाफ हैं। मैं चाहूंगा कि इस चेतावनी को सरकार जल्दी से जल्दी ग्रहण करे।

**Mr. Speaker:** I will call the hon. Member from Rajasthan. Shri Mathur (*Interruptions*).

**Some Hon. Members** *rose—*

**Pandit Thakur Das Bhargava** (Hissar): Sir, the question is the common concern of all States. (*Interruptions*). It is not a question of provincialism. The whole of Punjab is not a backward area. But there are areas in Punjab which are certainly much less advanced. So, it is not a question of States. (*Interruptions.*)

**Mr. Speaker:** I will call others also.

**श्री विभूति मिश्र** (बगहा) : उत्तर बिहार पिछड़ा हुआ एरिया है। पर हम को बोलने का समय नहीं दिया जाता। पंडित ठाकुर दास तो एग्रीकल्चर पर बोल चुके हैं, कम्युनिकेशन पर बोल चुके हैं और इस पर भी बोलना चाहते हैं। हमारे विधान में समानता का बरताव करने का विधान है। क्या इस में समानता नहीं बरती जायेगी ?

**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्र गढ़) : मैं ने भी अमेंडमेंट दिया है। मेरा एरिया भी बैकवर्ड है। मुझे चांस मिलना चाहिये।

**Mr. Speaker:** I am sorry that every hon. Member wants to represent some backward area. Not all areas of a particular State are backward. I will give them also an opportunity. There are States which are more backward; and there are States less backward. I will start with the more backward first. I will call the hon. Members one after the other. If necessary we will extend the time. Shri Mathur.

**Shri Harish Chandra Mathur** (Pali): Mr. Speaker, Sir....

**Mr. Speaker:** I will give opportunities to all backward areas.

**Shri Harish Chandra Mathur:** I will try to represent all backward areas. I will not refer only to regional viewpoints. The demands made in this resolution are unexceptionable. This policy has already been accepted by the Government and it is reflected in the various announcements and policy statements. You may take the Plan or the various other statements. Everywhere it has been stated that the backward areas will be given special treatment and

that they must be brought up to a particular level. Right from the Rashtrapathi, the Prime Minister and the planners—all these people have given this assurance. More particularly, when the former princely States were integrated, such a categorical assurance was given. It appears they now want to wriggle out of it some how because they say the whole country is backward. What is backward? They ask like that. This is a thing against which I raise my voice very strongly. It is a very unkind cut against an already accepted policy. Even today in the United Kingdom, they have a definite policy regarding certain areas and they give special preference to see that these undeveloped areas could come up. That is even in the United States. I would like them to understand what they have done in the U.S.S.R. Just across the border, in Tashkent, they have given special preference to that particular area during the last few years and it has come up. I hope that the Government will not back out from a definite policy statement which it has made. It is unfortunate that these policy statements have remained absolutely pious hopes and we have been living under a delusion or illusion that something will be done. I have got here from the Parliament Library a complete statement indicating how the Central Government during these ten years had catered the Central assistance; you will find from it that it is only the underdeveloped and backward areas which have got the most uncharitable treatment. I think they will ask how to determine or compare the backwardness. We know in Rajasthan the percentage of literacy in 1950 was 10 per cent.

**Shri Kalika Singh:** In U.P. also it is 10 per cent.

**Shri Harish Chandra Mathur:** In other places it was 30-40 per cent.... (*Interruptions.*) I represent all those areas. I am just giving it as an instance. Yet, if you look at it, you will find that Central assistance to Rajasthan on education is the least *per capita*. Let us look at the highways. You will again find that those areas which had been under-developed, there also the highways mileage is the shortest. You take again the railways. Those particular areas where we did not have these railways and which were under-developed, they are completely neglected. Out of twenty lines, hardly two or three lines were given. Then you take the Central educational institutions. They will not, for instance, take the Central engineering college to one of these backward areas. This is a policy which has been going counter to the policy statements made by the Government. You can judge things from these criteria. There is not one public enterprise established there. It could have been there. I could convince the hon. Minister about it. But let me not go into details. I only want to submit that the policy had been accepted but the Government is wanting to wriggle out of that policy.

Now, I come to concrete suggestions. It is no use our denouncing the Government and making general accusations and condemning the Plan. I would make some concrete suggestions so that we are not left in the same position even after the Third Plan. We now understand that in the Third Plan they propose an outlay of Rs. 6,500-7,000 crores for the public sector. I do wish that at least Rs. 500 crores are completely earmarked and kept separate. Let the remaining Rs. 6,500 crores be distributed according to the Plan. We must have a plan outlay. We must have a planned development. At those places where you have a definite advantage for certain industrial development you must have those industries there. I do not say that you should not do it. If a particular place is most suited for a particular industry you must have it there. But I would strongly urge that out of this Plan outlay Rs. 500 crores must be completely earmarked for the under-developed areas. I would also very much wish that we have a Cabinet Minister here

[Shri Harish Chandra Mathur]

at the Centre who will be in charge of the administration of these Rs. 500 crores which amount is to be set apart exclusively for the under-developed areas, apart from the allocations which are made in the Central Plan and the State plans. If that amount is kept in charge of a separate Cabinet Minister, he will see what to do.

Apart from that there are other steps which could positively be taken. Now, I understand that you will have a steel plant at a particular place.

**Shri Nanda:** Is the hon. Member suggesting that a Minister should administer it directly from here?

**Shri Harish Chandra Mathur:** No, Sir; through the States, but these Rs. 500 crores must be kept separate and administered by a Cabinet Minister here through the States as other plans are administered. What I am suggesting will be in addition to your plans and projects, and that amount will be utilised exclusively for the purpose of bringing up the under-developed areas. After all, the development of the entire country has to take place. I wish that there must be a planned development. We have to give a fillip to these under-developed areas. To give that fillip we have to give some special treatment to these under-developed areas, and for that I want that Rs. 500 crores should be earmarked with a Cabinet Minister in charge of it who will go into the question of their development.

**Shri Kalika Singh:** Will that be discretionary or budgeted?

**Shri Harish Chandra Mathur:** Sir, I will give another suggestion. There has been absolutely a vertical growth of our industry—that is there for historical reasons, I am not going into that. If you are planning the fourth steel plant, what I would suggest is that the plant should be, as a matter of fact, planned in such a manner that you have the original plant at the place selected but you set up at least the ancillary industries to support that in the backward areas. It is nothing new, it is done everywhere. I wish that all the public sector enterprises, all the public sector projects should have these ancillary industries. These ancillary industries should be set up in the backward areas. There must be an industrial estate of 20 to 30 units to cater to a particular plant, and that industrial estate should be set up certainly in one of the backward or under-developed areas.

We are now thinking of manufacturing cars. If you go into that question you will find that the Jha Committee which went into that question has said that the project has suffered because the ancillary industries were not properly developed, because they were not drawing most of their components from ancillary industries in the country.

Our projects should be planned in such a manner that you have a number of industrial estates which are to be feeders of the big projects and those industrial estates should be located in the under-developed areas. The Railways can do it, because they take quite a number of stores. Similarly, the Central Government can also see that a number of small industries grow in those areas.

Out of the Rs. 500 crores which I have suggested, they must devote a sizable part of it—Rs. 25 crores to Rs. 50 crores—for settling up nursery sets for power generations in those under-developed areas where power is not likely to reach otherwise, so that industries can grow there. Apart from that, we can give special incentives so that industries can grow in those areas; otherwise, industries have definitely a tendency to go to other places where those advantages exist at present. I do not want to drive any industry to any disadvantageous area, but these temporary disadvantages which are there because of

earlier development should be outweighed by certain incentives which you give to counter-balance those temporary disadvantages so that industries can grow there. In the under-developed areas, more particularly in the rural areas where the population is below 5,000, you can give them a tax holiday. Then you can entrust the work to a particular Ministry. When a tax holiday is given there, say, for about five years, naturally, the industry will be attracted to those places. Then you can give certain concessions in the sales tax.

There is another important thing that you could do, namely, you should make the raw material available in those areas.

**Mr. Speaker:** Has any survey been made of all the under-developed areas in the whole of India, in various States, in order that priority could be given to them?

**Shri Nanda:** Would you like me to say something about it at this stage?

**Mr. Speaker:** No. I enquired whether any survey has been made.

**Shri Nanda:** Surveys are being made in various States.

**Shri Sinhasan Singh:** On paper everything is good!

**Shri Harish Chandra Mathur:** Even at present, you have got schemes and organisations for making surveys. Apart from that, as I submitted earlier, you must remember that there are under-developed areas in countries like the United Kingdom and the U.S.A. also. They have got under-developed or depressed areas, even at the present stage of development in those countries. And they are giving special treatment to those parts. We have got a report about the industrial establishments in the United Kingdom. It is a revealing document, and in it you will find that hidden subsidies and open subsidies are given to see that the depressed areas come up. These subsidies are given both for developing those areas and also for dispersal of the industries. So, such methods could be adopted by the Ministry in this country. There are certain scarce raw materials. For instance, I would like to set up an industry in an under-developed area, but you do not encourage me for this. You say that "I will give you some amount and the raw materials also if you go and settle in a town with a population of just 5,000 and start a small scale industry there". Then, naturally, I would like to do that and settle there. Of course, electricity must be made available. Then I will have certain disadvantages also, because such things as have developed in the urban area will not be available in the rural area.

But then, a tax holiday could be given. The raw materials should be made available. Certain power plants and nursery plants could be made available there. Various other measures could be adopted. You will find from the various reports what steps could be adopted. Only yesterday, a report was submitted by the Estimates Committee wherein they came to the conclusion that it is really unfortunate that there has been no dispersal of industries. It is natural. There is not going to be any dispersal of industries unless and until you take certain positive steps to see that industries are attracted to those areas and are dispersed. The greatest malady and the greatest failure of the Planning Commission and our Plan projects is that there has been no dispersal of industries. That is why there is a regular exodus from the rural areas to the towns. We have been indulging in tall talk. I say it is no use making general observations. Let us think what positive steps should be taken. Let us understand from the Planning Commission what positive steps they have taken to give effect to the policy resolution. I say it is absolutely none. That is why I have suggested to them that very positive steps should be taken to develop the under-developed areas and effect a dispersal of industries.

**Mr. Speaker:** Any one hon. Member representing Madhya Pradesh may speak now.

**Shri R. C. Sharma** (Gwalior) *rose*—

**Mr. Speaker:** Is he from Madhya Pradesh.

**Shri R. C. Sharma:** Yes, Sir.

**Mr. Speaker:** All right. Let him go on. We will adjourn at 6.35.

**श्री रा० च० शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इस सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है, उस के लिये मैं श्री द्विवेदी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने आज इस विषय को प्रस्तुत कर के इस सदन के सामने एक ऐसा अवसर उपस्थित किया है कि इस पर विचार करते हुए हम अपने योजना मंत्री का ध्यान देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास की ओर अच्छी तरह से दिला सकते हैं । मैं यह जानता हूं कि हमारे योजना मंत्री जी अध्यात्मवादी हैं और पूज्य महात्मा जी ने इस देश के ग्रामों को इस देश की आत्मा बतलाया था । तो आत्म-कल्याण के लिये उन का प्रयत्न होना स्वाभाविक है । इस देश का जो पिछड़ा भाग है, वे अधिकांशतः ग्राम हैं, मैं समझता हूं कि उनका विकास होना उन के जो विचार आत्म-कल्याण के हैं, उन के समतुल्य हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में पिछड़े हुए भाग जिन को हम कह सकते हैं उन को इस प्रकार से आंका जा सकता है कि पहले तो वे हैं कि वहां पर गरीबी है, निरक्षरता है और उद्योग धंधों का अभाव है और दूसरे वे हैं जहां पर जीवन में सादगी नहीं, जीवन में प्रेम नहीं और जीवन में सात्विकता नहीं है । यदि इस दूसरी परिभाषा को लिया जाये तो सारे का सारा देश पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो जाता है । एक ओर ग्रामीण इलाके हैं जहां पर उद्योग-धंधों का अभाव है, गरीबी है, निरक्षरता है और दूसरी ओर शहर हैं जहां पर कि न सादगी है, न प्रेम है और सात्विकता का भी अभाव है ।

लेकिन मैं इस समय पर इस प्रस्ताव को पेश करने वाले जो माननीय सदस्य हैं और जो उनका अभिप्राय है तथा जो प्रस्ताव की भाषा है, उस को ले कर ही कुछ निवेदन करना चाहता हूं । उन के प्रस्ताव में आर्थिक विकास को ले कर के पिछड़ा हुआ क्षेत्र जिस को आंका गया है, जिस को ले कर वे चले हैं, उन की ओर ही आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस देश में जो अधिकतर पिछड़े हुए भाग हैं यदि उन को देखा जाये, तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा राज्य जिस का नाम मध्य प्रदेश है और जो करीब एक हजार मील लम्बा है और . . . . .

**Mr. Speaker:** The hon. Member will continue his speech on the next day.

**18.37 hrs.**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 28, 1960/Chaitra 8, 1882 (Saka).*